सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 42, नई दिल्ली । बुधवार, 24 अप्रैल 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं।

03 दिल्ली में आंधी-बारिश से आफत, चार मंजिला घर के छत की दीवार पड़ोसी के मकान पर गिरी
06 आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता दवा क्षेत्र
08 लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान की दिलाई शपथ

दिल्ली में एक ही नम्बर के 2 या उससे भी अधिक सड़कों पर चल रहे आटो तीन पहिया, कैसे और कौन जिम्मेदार, बड़ा सवाल ?

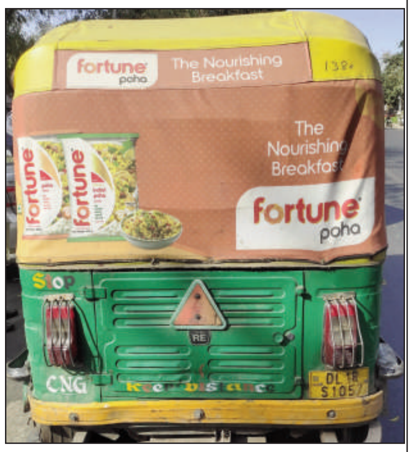

संजय बाटला

नई दिल्ली। 22 अप्रैल 2024 को परिवहन आयुक्त से आटो तीन पहिया यूनियंस से हुई बैठक में आटो परिवार द्वारा सड़क एवम्‌सवारी सुरक्षा के प्रति एक बड़ा मुद्दा उठाया। आटो परिवार के अध्यक्ष इंदरजीत सचदेवा के द्वारा उठाए गए मुद्दे की सत्यता इससे भी सिद्ध होती है कि पहले भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एवम अन्य कई स्थानों पर पुलिस द्वारा एक ही नम्बर के दो आटो तिपहिया पकड़े जा चुके हैं, पर फिर भी परिवहन विभाग, उसके आला अधिकारी, प्रवर्तन शाखा परिवहन विभाग, दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली पुलिस जनता की सुरक्षा के प्रति जागरूक नही हुए और ना ही इसे रोकने के प्रति कोई ठोस कदम उठाया। सबसे बड़ी अचंभित करने वाली बात जो सामने बार बार आ रही है वह है दोनो ही आटो पर एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगी हुई होती है और साथ ही दोनो ही आटो में परिवहन विभाग द्वारा जारी ओरिजनल कागजात (आरसी, परमिट, फिटनेस इत्यादि) भी उपलब्ध होते है, आख़िर कोन है इसका मास्टरमाइंड जो बड़ी चालाकी से सभी कार्य करवा लेता है और सड़को पर जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ के लिए ऐसे आटो उपलब्ध करवाता है। आटो परिवार के अध्यक्ष इंदरजीत सचदेवा द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर **परिवहन आयुक्त द्वारा जितनी गंभीरता दिखाई गई वह तारीफे काबिल थी।** आटो परिवार के अध्यक्ष द्वारा संवाददाता को बताया गया की बैठक में ही तत्काल प्रभाव से **परिवहन आयुक्त ने टू-व्हीलर टैक्सी ओर उनके एग्रीगेटर कम्पनियों के खिलाफ अभियान चलाने ओर अवैध एचएसआरपी जारी करने वालो पर शिकंजा कसने के साथ ऑटो रिक्शा को इंजिन ओर चैसिस नम्बर द्वारा जांच कर दोषी ऑटो को जब्त करने के निर्देश जारी किए।** पर वही **विशेष परिवहन आयुक्त द्वारा इस मुद्दे को टालने के लिए जो प्रयास किए गए वह सोचनीय है।** क्या जनता की सुरक्षा से भी बड़ा या महतवपूर्ण कोई मुद्दा हो सकता है। **एसटीए सचिव उर्फ विशेष आयुक्त आटो टेक्सी शाखा उर्फ विशेष आयुक्त प्रवर्तन शाखा उर्फ विशेष परिवहन आयुक्त दिल्ली के लिए ऐसी जानकारी प्राप्त होने के साथ ही इस मुद्दे पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की जगह इसे टलवाने की कोशिश करना यह सिद्ध करने के लिए काफी है कि उनके लिए दिल्ली की जनता खास तौर से महिला की सुरक्षा कितना महत्व रखती है।**

दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एंड टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 2024 क़ो प्रेस क्लब ऑफ़ इंडिया, रायसीना रोड मे 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली। लोकसभा 2024 के चुनाव के बहिष्कार की घोषणा और बहिष्कार करने के पीछे के क्या है कारण, बताएंगे। लगभग 10 सालो से उनके द्वारा उठाई जा रही जायज मांगो को सरकारों द्वारा अनुसूना किया जाता रहा हैं और साथ ही

1:- पैनिक बटन के नाम पर परिवहन विभाग दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिको से करोंड़ो रूपए का भ्रष्टाचार करता आ रहा हैं.

2:- स्पीड लिमिट डिवाइस जो सिर्फ दिल्ली के व्यवसायिक वाहनों पर लागू किया हुआ है उसके (स्पीड गवर्नर) कारण महिलाओ की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा हैं, महिलाओ के साथ बलात्कार होने की संभवाना हो रहीं हैं और उनकी जानमाल को खतरा बना रहता है.

3:- दिल्ली में ही पंजीकृत वाहनों से एमसीडी टोल टैक्स और ग्रीन टैक्स के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा हैं

4:- प्रदूषण के नाम पर गाड़ियों को स्क्रैप (कूड़ा)बनाया जा रहा हैं.

एसोसिएशन अध्यक्ष द्वारा नम्र निवेदन किया गया हैं की दिंनाक 24.04.2024 को समय 3 बजे

आप जरूर आये. वहाँ वह और उनके ने साथी तफ्तीश से अपनी समस्याओ से अवगत कराएँगे और प्रेस/मिडिया के समक्ष ही लोक सभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा भी करेंगे और बताएंगे की क्यों वह सब एकजुट होकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं।

परिवहन विभाग द्वारा 1आरटी वाहनों की परिवहन विभाग की गलती से रुक रही फिटनेस के लिए नही प्रदान किया कोई हल

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। आप परिवार के अध्यक्ष इंदरजीत सचदेवा द्वारा बताया गया की दिनांक 1/4/2024 से दिल्ली सरकार द्वारा जीपीएस के लिए सिम कार्ड नही उपलब्ध करवाने की वजह से DL1RT ओर इस प्रकार की टैक्सियों की फिटनेस नही हो पा रही है। दरअसल ऑटो रिक्शा की तरह ही टैक्सियों को भी जीपीएस ट्रैकिंग हेतु जीपीआरएस सिम कार्ड दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है जिसकी कीमत 584/ होती है। दिल्ली सरकार द्वारा सिम कम्पनियों वोडाफोन/आईडिया को इसकी कीमत अदा करती है परन्तु पिछले काफी समय से सरकार द्वारा डिम्ट्स एवं सिम कम्पनी को इसकी कीमत अदा नही की गई है जिस कारण सिम कम्पनी ने अब सरकार को उधार देने से इनकार कर दिया है।

ड्राइवर यदि कीमत अदा कर सिम कार्ड खरीदता है तो डिम्ट्स उसकी ट्रैकिंग को साफ मना कर रही है। डिम्ट्स का कहना है कि नगद खरीदे गए सिम पर हम एक्टिवेशन नही दिखा सकते क्यों कि कैबिनेट के फैसले के कारण हम फ्री वाली सिम पर ही एक्टिवेशन दे सकते हैं ड्राइवर परेशान है सरकार के फ्री वाले लॉलीपॉप से।

वह चाहता है कि किसी प्रकार उसकी टैक्सी चले। वह सिम के पैसे देने को तैयार है क्योंकि आज 23 दिन हो चुके है फिटनेस के बिना, **परिवहन विभाग इस पर तत्काल संज्ञान ले और हल दे।**

सड़क सुरक्षा पाठशाला : "भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति- एक गंभीर वास्तविकता"

-डॉ अंकुर शरण

भारत, अपनी व्यस्त सड़कों और राजमार्गों के साथ, दुर्भाग्य से आश्चर्यजनक संख्या में सड़क दुर्घटनाओं का भी घर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, हर साल भारतीय सड़कों पर लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है, जिनमें से एक तिहाई मौतें अकेले राष्ट्रीय राजमार्गों पर होती हैं। वैश्विक मोटर वाहनों में केवल 1% का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद, भारत में सड़क यातायात से होने वाली कुल मौतों में से 11% से अधिक मौतें होती हैं, यह एक गंभीर आँकड़ा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

लैंसेट की एक हालिया रिपोर्ट स्थिति की गंभीरता को और भी रेखांकित करती है, जिसमें खुलासा किया गया है कि दुनिया भर में कुल वाहनों की संख्या का केवल 1% होने के बावजूद, भारत दुनिया भर में सभी दुर्घटना-संबंधी मौतों में लगभग 10% का योगदान देता है। यह असमानता चिंताजनक है और इन दुखद घटनाओं के पीछे के मूल कारणों की गहन जांच के लिए प्रेरित करती है।

ROAD ACCIDENTS IN INDIA

Year	Road Accidents	Deaths	National Highway Accidents	Deaths	Deaths per 100 km on NHs
2017	4,45,730	1,50,093	1,30,942	50,859	NA
2018	4,45,514	1,52,780	1,28,573	50,771	44
2019	4,37,396	1,54,732	1,28,602	53,213	47
2020	3,54,796	1,33,201	1,06,933	45,275	36
2021	4,03,116	1,55,622	1,22,204	53,615	40

Source NCRB

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की उच्च दर में कई कारक योगदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:

तेज़ गति और अनुशासनहीन ड्राइविंग: देश में लगभग 50,000 दुर्घटनाओं का कारण तेज़ गति से गाड़ी चलाना है, जो गति सीमा को सख्ती से लागू करने और ड्राइवर शिक्षा में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

मोटरीकरण और शहरीकरण: मोटर वाहनों और शहरी विकास में तेजी से वृद्धि के कारण सड़कों पर भीड़भाड़ हो गई है और पैदल चलने वालों और मोटर चालकों के लिए जोखिम बढ़ गया है।

दोषपूर्ण सड़क डिज़ाइन: अपर्याप्त सावधानी संकेत, गड्ढे और अवैध स्पीड ब्रेकर ड्राइवरों के लिए खतरनाक स्थितियाँ पैदा करते हैं और दुर्घटनाओं की संभावना को बढ़ाते हैं।

कमजोर वाहन सुरक्षा मानक: घटिया सुरक्षा नियम दुर्घटनाओं में लगी चोटों की गंभीरता में योगदान करते हैं, जो सभी वाहनों के लिए कड़े सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर देते हैं।

अप्रभावी सड़क नियम: उचित संकेत और सड़क रखरखाव की कमी से टकराव का खतरा बढ़ जाता है और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों में बाधा आती है।

सड़कों का अतिक्रमण: अनधिकृत विक्रेता और भीड़ यातायात के प्रवाह को बाधित करते हैं, जिससे ड्राइवरों के लिए चुनौतियाँ पैदा होती हैं और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।

ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में ढिलाई: ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी सड़कों पर अकुशल ड्राइवरों की व्यापकता में योगदान देती है, जिससे योग्यता और सुरक्षा के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

अकुशल सार्वजनिक परिवहन: विश्वसनीय और सुलभ सार्वजनिक परिवहन विकल्पों की कमी निजी वाहनों पर निर्भरता को बढ़ावा देती है, जिससे सड़कों पर भीड़भाड़ होती है और दुर्घटना दर में वृद्धि होती है।

सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव

सड़क दुर्घटनाओं के परिणाम महज़ आँकड़ों से परे होते हैं, जो समाज, अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं:

सामाजिक प्रभाव: सड़क यातायात दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पादकता में कमी, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर दबाव और पीड़ितों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है।

आर्थिक प्रभाव: संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सड़क यातायात में होने वाली मौतों और चोटों को कम करने से दीर्घकालिक आय में महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर दुर्घटनाओं के आर्थिक नुकसान को उजागर करता है।

महिलाओं पर बोझ: विशेष रूप से महिलाओं को दुर्घटनाओं के बाद एक महत्वपूर्ण बोझ उठाना पड़ता है, कई महिलाओं को अपने रोजगार और पारिवारिक जिम्मेदारियों में बदलाव का अनुभव होता है, जो व्यापक सहायता प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें बेहतर बुनियादी ढांचे, नियमों का सख्त प्रवर्तन, बेहतर चालक शिक्षा और सार्वजनिक परिवहन में अधिक निवेश शामिल है। केवल ठोस प्रयासों से ही हम सड़क दुर्घटनाओं के विनाशकारी प्रभाव को कम करने और सभी के लिए सुरक्षित सड़कें बनाने की उम्मीद कर सकते हैं।

डॉ अंकुर शरण, राष्ट्रीय मुख्य यातायात एवं नियोजन अधिकारी, सड़क सुरक्षा ओमनी फाउंडेशन

राय / शिकायत और सुझाव

सड़क दुर्घटनाओं के दो प्रमुख कारण
गलत साइड ड्राइविंग
विशेषकर रात में सर्विस लेन पर ट्रकों/डम्परों की गलत पार्किंग

मेरा सुझाव:
इन दोनों उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस, आरटीओ और अन्य हितधारकों द्वारा 15 दिनों का अभियान चलाया जाना चाहिए
सभी यात्रियों से अपील है कि वे रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के दौरान आवाजाही से बचें। मेरे अध्ययन के अनुसार अधिकांश दुर्घटनाएँ इसी अवधि में होती हैं।
एक सुझाव जो मैं हमेशा सभी से अपील करता हूं।
-शादियों में देर रात घूमने से बचने के लिए हमें शाम के फेरों को बढ़ावा देना चाहिए। मैंने विवाह के बाद देर रात/शुरूआती गतिविधियों में नजदीकी लोगों में मौतें देखी हैं।

सीए तरुण गुप्ता

सड़क सुरक्षा पाठशाला : द डेडली डांस: रोड रेज और ओवरस्पीडिंग रोमांच

आधुनिक जीवन की अराजक सिम्फनी में, जहां समय एक बहुमूल्य वस्तु और एक अथक कार्यकर्ता दोनों है, सड़कें अक्सर अधीरता और आक्रामकता के बीच एक खतरनाक नृत्य का मंच बन जाती हैं। रोड रेज और ओवरस्पीडिंग, वाहन जोखिम के दोहरे भूत, हमारे राजमार्गों और उपमार्गों पर मंडराते हैं, और अपने पीछे विनाश और बर्बादी छोड़ जाते हैं।

रोड रेज, हताशा और अनियंत्रित क्रोध से प्रेरित वह द्वेषपूर्ण शक्ति, डामर के शांत विस्तार को गुस्से के युद्ध के मैदान में बदल देती है। यह व्यक्तियों को तर्क करने से अंधा कर देता है, छोटी-मोटी असुविधाओं को जीवन-घातक टकराव में बदल देता है। हॉर्न बजाना, आक्रामक हाव-भाव और लापरवाह चालें इस बेहूदा झड़प में हथियार बन जाते हैं, जिससे कोई विजेता नहीं बचता, केवल पीड़ित बच जाते हैं। फिर भी, अराजकता के बीच, एक सरल सत्य बना हुआ है: दयालुता की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इसकी अनुपस्थिति से सब कुछ महंगा पड़ सकता है।

स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ ओवरस्पीडिंग का आकर्षण है, एक सायरन गीत ड्राइवरों को अपने वाहनों की सीमा और उनकी मृत्यु दर का परीक्षण करने के लिए लुभाता है। वेग का रोमांच इंद्रियों को नशे में डाल देता है, निर्णय को धूमिल कर देता है और संभावित तबाही की गंभीर वास्तविकताओं को अस्पष्ट कर देता है। लेकिन सच तो यह है: गति क्षणिक दौड़ प्रदान कर सकती है, लेकिन इसके परिणाम एड्रेनालाईन के ख़त्म होने के बाद लंबे समय तक बने रहते हैं। जिंदगियाँ बिखर गईं, परिवार टूट गए, भविष्य ख़त्म हो गया - सब कुछ पलक झपकते ही।

मिनट बचाने की आपाधापी में, हम अक्सर जीवन के मूल्य को ही भूल जाते हैं। शिक्षा, अनुभव और विशेषाधिकार का कोई मतलब नहीं है अगर वे सड़क पर हमारे व्यवहार को संयमित नहीं कर सकते। विनम्रता, धैर्य और सम्मान के साथ की गई प्रत्येक यात्रा संवेदनहीन हिंसा और त्रासदी के ज्वार के खिलाफ एक जीत है।

तो, आइए हम सड़कों पर विनम्र बने रहने, आक्रामकता पर दया को अपनाने और यह पहचानने के आह्वान पर ध्यान दें कि लापरवाह जल्दबाजी की लागत की तुलना में देर से आना एक छोटी सी कीमत है। आइए हम अपनी सुरक्षा और अपने आस-पास के लोगों की सुरक्षा के लिए गति के आकर्षण को अस्वीकार करें। अंत में, यह वह गति नहीं है जिससे हम यात्रा करते हैं जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि वह तरीका है जिससे हम जीवन की यात्रा करते हैं।

डॉ अंकुर शरण,
सड़क सुरक्षा ओमनी फाउंडेशन

जन साधारण को सूचना : यातायात पुलिस गुरुग्राम ने शंकर चौक पर किया नया ट्रैफिक ट्रायल शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा आमजन की सुविधा और यातायात के सफल व सुगम संचालन के लिए सोमवार को IFFCO चौक से गोल्फ कोर्स रोड पर जाने वाले वाहनों के लिए AMBIANCE MALL के पास बने अंडरपास में सीधा भेजने का ट्रायल शुरू किया था। जो एंबिएंस मॉल के पास बने अंडरपास की क्षमता को देखते हुए कि अंडरपास के रास्ते वाहनों को अधिक समय लगने के कारण आज स्वयं पुलिस उपायुक्त यातायात श्री विरेंद्र विज IPS, सहायक पुलिस उपायुक्त यातायात मुख्यालय/हाईवे श्री सुखबीर सिंह HPS, यातायात निरीक्षक राजेंद्र, RSO केशिका, जगदीश और राजीव नंदवानी ने मौका पर जाकर निरीक्षण किया और मौजूद सभी लोगों की राय/सहमती से यात्रियों के लिए इसको चौक से होकर गोल्फ कोर्स रोड पर जाने वाले वाहनों के लिए एंबिएंस मॉल से पहले यू टर्न को खोल दिया गया ताकि जो वाहन इफको चौक से होकर गोल्फ कोर्स रोड पर जाएंगे वे सभी वाहन चालक अंडरपास से ना जाकर एंबिएंस माल से पहले बने यू टर्न से ही मुड़कर सीधा गोल्फ कोर्स रोड पर जा सके और उनका कीमती समय भी बचाया जा सके। इसलिए आमजन को यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा हिदायत दी जाती है कि इफको चौक से आने वाले वाहन एंबिएंस माल से पहले बने यू टर्न का ही इस्तेमाल करके सीधा गोल्फकोर्स रोड पर जायेंगे और एंबियंस मॉल अंडरपास का इस्तेमाल नहीं करेगें। यह नया ट्रायल आज मंगलवार दिनांक 23.04.2024 से शुरू किया गया है।अगर यह ट्रायल कामयाब रहा तो इसे स्थाई तौर पर लागू भी किया जाएगा।

शरीर की प्रकृति के हिसाब से सेवन करें मिलेट्स, वात, पित और कफ दोष में कौने-से मिलेट्स खाना सही होता है?

मिलेट्स का सेवन आप सभी करते है, लेकिन क्या आप जानते है? इसे शरीर की प्रकृति के अनुसार सेवन करना जरुरी है। यहां इस लेख में हम बताएंगे कि वात,पित्त और कफ दोष में कौन-कौन से मिलेट खाना सही होता है। वैसे तो मिलेट्स सेहत के लिए बढ़िया होते है लेकिन शरीर की प्रकृति के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए।

स्वस्थ रहने के लिए आजकल डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को मिलेट्स खाने की सलाह देते हैं। गौरतलब है कि भारत सरकार भी हेल्दी मिलेट्स की दुनियाभर में प्रचार कर रही है। इसी वजह से लोग मिलेट्स को लेकर जागरुक हो रहे हैं और डाइट में मिलेट्स जरुर शामिल करें। इसके सेवन से शरीर को विटामिन, खनिज और फाइबर अच्छी मात्रा मे मिलते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक, शरीर की प्रकृति के अनुसार मिलेट्स यानी मोटे अनाज का सेवन करें।

वात प्रकृति में कौन-सा मिलेट खाएं?

डॉक्टर के मुताबिक, जिन लोगों के शरीर में वात प्रकृति होती है या जिन्हें ज्यादा ठंड लगती है उन सभी लोगों को अपनी डाइट में बाजरा शामिल करना चाहिए। क्योंकि बाजरा गर्म तासीर का मिलेट है, जिससे आपके शरीर में वात दोष कंट्रोल हो सकता है। बाजरा ग्लूटन फ्री होता है और वेटलॉस में काफी फायदेमंद होता है। इसके अलावा डायबिटीज भी कम हो सकती है।

पित्त प्रकृति में कौन-सा मिलेट खाएं?

जिन लोगो के शरीर में पित्त प्रकृति होती है या जिनके शरीर में बेहद गर्मी होती है उन्हें ज्वार का सेवन करना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि ज्वार की तासीर काफी ठंडी होती है। ज्वार के सेवन से शरीर पित्त को शांत करता है और वात को बढ़ाता है। वहीं इसके सेवन से कई पोषक तत्व हैं, जैसे फॉस्फोरस, आयरन और पोटेशियम आदि। इसमें विटामिन बी-कॉम्पलेक्स और प्रोटीन भी पाया जाता है।

कफ प्रकृति में कौन-सा मिलेट खाना सबसे बेहतर हैं

रागी का सेवन तीनों यानी कफ, वात और पित्त प्रकृति के लोग कर सकते हैं। क्योंकि इसकी तासीर न ठंड़ी होती है और न ही गर्म होती है। रागी का सेवन करने से कई फायदे होते है। इन मिलेट्स को आप अपनी डाइट में जरुर शामिल करें।

क्या आपके बच्चे में भी हैं सेंसरी सीकिंग के लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

बच्चों का चुलबुलापन और शरारतें भला किसे पसंद नहीं होती हैं। वहीं उम्र बढ़ने के साथ ही बच्चों के शरीर में कई तरह के शारीरिक और मानसिक विकास भी होते रहते हैं। जिस तरह से धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे-वैसे उनकी इंद्रियों की क्षमता भी विकसित होने लगती है। बच्चे जब बचपन में इंद्रियों में संवेदी अनुभव की तलाश करना शुरू करते हैं। तो बच्चे हर चीज की तरफ आकर्षित होने लगते हैं।

हांलाकि सभी बच्चों में एक जैसी गतिविधियां नहीं पाई जाती हैं। इस तरह की स्थिति को सेंसरी सीकिंग कहा जाता है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बच्चों में होने वाले सेंसरी सीकिंग के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

क्या है Sensory Seeking

आपको बता दें कि बढ़ती उम्र के साथ ही बच्चे स्वाद, ध्वनि, गंध, दृष्टि और स्पर्थ जैसी चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। वह धीरे-धीरे इन चीजों को जानते और समझते हैं। हांलाकि सभी बच्चों में यह स्थिति समान नहीं होती है। जहां कुछ बच्चे खेलकूद के प्रति आकर्षित होते हैं, तो वहीं कुछ बच्चों का किसी खास तरह के म्यूजिक और कुछ का खाने-पीने की चीजों की तरफ आकर्षण होता है। इस स्थिति को ही सेंसरी सीकिंग कहा जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुछ बच्चों में सेंसरी सीकिंग से जुड़ी कुछ परेशानियां भी होती हैं।

सेंसरी सीकिंग से जुड़े लक्षण

- गले लगने में हिचकिचाना
- किसी की गोद में न जाना
- वस्तुओं को छूना या सहलाना
- स्थिर बैठने में परेशानी होना
- हाइपर एक्टिव होना
- ऊँचे स्थानों से कूदना
- बार-बार चीजों को मुंह में डालना

बच्चों में इस तरह के लक्षण दिखने पर उनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे उनके कई तरह की परेशानियों का खतरा बढ़ जाता है। बता दें कि सेंसरी सीकिंग से जुड़ी स्थितियां बच्चों को इंद्रियों को ट्रिगर कर सकती हैं। सेंसरी सीकिंग के कारण बच्चों में स्पर्श, लाइट, साउंड और गंध आदि से जुड़ी परेशानियों का खतरा होता है।

वेट लॉस के लिए डाइट में इस तरह से शामिल करें ये दालें, जल्द दिखने लगेगा असर

आजकल बढ़ता वजन एक आम समस्या हो गई है। वेट लॉस के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। मोटे और थुलथुले पेट को हटाने के लिए लोग योग, एक्सरसाइज और महंगे-महंगे डाइट प्लान फॉलो करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वेट कम करने के लिए फैंसी डाइट प्लान फॉलो करने और सही खानपान फोकस करने की जरूरत होती है। वहीं घर में मौजूद कुछ चीजें भी वेट लॉस में बेहद फायदेमंद होती हैं। इन्हीं में से एक हैं दालें।

दालों में प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनके सेवन से वजन और मोटापा आसानी से कम करने में मदद मिलती है। लेकिन किन दालों के सेवन से वेट लॉस में मदद मिलती है, इस बारे में भी सही जानकारी होना जरूरी है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन दालों के सेवन से आप आसानी से अपना वेट लॉस कर सकते हैं।

मूंग दाल

वेट लॉस के लिए मूंगदाल बेस्ट मानी जाती है। मूंग दाल में विटामिन-सी, विटामिन बी-6, आयरन, फाइबर, फोलेट, राइबोफ्लेविन, मैग्नीशियम,पोटैशियम, कॉपर, फास्फोरस, नियासिन और थायमिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। फाइबर युक्त होने की वजह से मूंग दाल वेट लॉस और मोटापा घटाने में लाभकारी होती है। एक्सपर्ट्स की मानें, तो फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद करती है। इससे आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं और वजन कम करने में मदद मिलती है। बता दें कि मूंग दाल में लो कैलोरी पाई जाती है। इसको खाने से वेट लॉस होता है। आप मूंग दाल का चीला, इडली, खिचड़ी, स्प्राउट्स और सूट को डाइट में शामिल कर सकते हैं।

मटर की दाल

कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि मटर दाल का सेवन करने से आप आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आप तेजी से वेट कम करना चाहते हैं तो मटर की दाल और इससे बनी डिशेज अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। क्योंकि मटर दाल में फाइबर और एमाइलोज नामक स्टार्च पाया जाता है। जो भूख को कंट्रोल करने में मदद करती है। मटर की दाल में विटामिन, प्रोटीन, जिंक और आयरन आदि पाया जाता है, जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देता है। इसका सेवन करने से बीमारियों का खतरा भी कम होता है।

ब्लैक बीन्स

ब्लैक बीन्स में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। यह वेट लॉस में काफी मदद करती है। एक्सपर्ट्स की मानें, तो ब्लैक बीन्स में रेसिसेंट स्टार्च पाया जाता है, जो भूख को शांत करता है। इतना ही नहीं इसमें फाइबर होने की वजह से पेट लंबे समय तक भरा रहता है। ब्लैक बीन्स को आप सूप, सलाद और टैकोस में मिलाकर अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं।

क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा कब लिखी गई थी? यदि नहीं, तो पता करें, शायद यह बात कम ही लोग जानते होंगे?

सभी लोग पवनपुत्र हनुमानजी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि यह कब, कहां और कैसे लिखा गया था। बात ए.डी. 1600 यह काल अकबर और तुलसीदासजी के समय का था। एक बार तुलसीदास जी मथुरा जा रहे थे, रात होने से पहले वे आगरा में रुके, लोगों को पता चला कि तुलसीदास जी आगरा आये हैं। यह सुनकर लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। जब बादशाह अकबर को इस बात का पता चला तो उन्होंने बीरबाला से पूछा कि ये तुलसीदास कौन हैं? तब बीरबाला ने अकबर को बताया कि उन्होंने रामचरितमानस का अनुवाद किया है। ये रामभक्त तुलसीदास जी हैं, मैं भी इनके दर्शन करने आया हूँ, इनकी अद्भुत एवं अलौकिक छवि है। अकबर ने भी उनसे मिलने की इच्छा जताई और कहा कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं। बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों की एक टुकड़ी तुलसीदासजी के पास भेजी और उन्होंने तुलसीदासजी को बादशाह का संदेश भेजा कि आप लाल किले पर उपस्थित हों। यह संदेश सुनकर तुलसीदासजी ने कहा, मैं भगवान श्री राम का भक्त हूं, मेरा सम्राट और लाल किले से क्या संबंध है? उन्होंने लाल किले पर जाने से साफ इनकार कर दिया। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो वह बहुत परेशान हुए और बादशाह अकबर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने तुलसीदासजी को जंजीरों में बांधकर लाल किले में लाने का आदेश दिया। बीरबाला ने अकबर को ऐसा न करने की सलाह दी लेकिन अकबर ने इसे स्वीकार नहीं किया और उन्होंने तुलसीदास को जंजीरों में बांधकर लाने का आदेश दिया। जब तुलसीदासजी को जंजीरों में जकड़ कर लाल किले में लाया गया तो अकबर ने कहा कि तुम एक करिश्माई व्यक्ति हो, कुछ करिश्मा दिखाओ और भाग जाओ। तुलसीदासजी ने कहा-

मैं केवल भगवान श्री राम का भक्त हूं, कोई जादूगर नहीं जो आपको कुछ करिश्मा दिखा सकूं। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो गया और उन्हें जंजीरों से बाँधकर कालकोठरी में डालने का आदेश दिया। अगले दिन, सैकड़ों बंदरों ने आगरा के लाल किले पर हमला कर दिया और पूरे किले को नष्ट कर दिया। लाल किले में हर तरफ अफरा-तफरी मच गई, तब अकबर ने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल यह क्या हो रहा है ? तब बीरबल ने कहा, हुजूर, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, लेकिन आप नहीं माने

और ये करिश्मा हो गया. अकबर ने तुरंत तुलसीदास को कालकोठरी से बाहर निकाला और जंजीरें खुल गईं. तुलसीदासजी ने बीरबल से कहा कि मुझे बिना दोष के दंड दिया गया है। कालकोठरी में प्रभु श्रीराम और हनुमानजी की याद आई। मुझे रोना आ रहा था और रोते हुए मेरे हाथ अपने आप कुछ लिख रहे थे यह 40 चौपाइयां, चालीसाएं हैं हनुमान जी से प्रेरित। तुलसीदास जी ने जेल से छूटते समय कहा था, जैसे हनुमानजी ने मुझे जेल में संकट से बाहर निकाला था, उसी प्रकार जो कोई संकट या परेशानी में है और इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके सभी दुख और सभी संकट दूर हो जाएंगे। इसे हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। अकबर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने तुलसीदासजी से माफ़ी मांगी और उन्हें पूरा सम्मान और सुरक्षा देते हुए मथुरा भेज दिया।

आज हर कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। और इन सभी पर हनुमान जी की कृपा है और सभी की परेशानियां दूर हो रही हैं। *इसलिए हनुमानजी को ₹संकट मोचन₹ भी कहा जाता है।

ऐसा देश जहां एक भी सांप मौजूद नहीं है, जंगल की भी नहीं है कमी, फिर भी

दुनिया के अनोखे जानवरों में से एक सांप भी है और यह करीब 6 लाख साल पहले आए महाविनाश के बाद धरती पर पनपने लगे थे। अपने जहर के लिए यह सांप मसहूर हैं और यह दुनिया के हर देश में लगभग पाए जाते हैं। भारत को दुनिया में सापों का देश भी कहा जाता है। यह कल्पना करना मुश्किल है कि कोई भी ऐसा देश मौजूद हो सकता है, जहां पर सांप नहीं हो। लेकिन एक ऐसा देश इस धरती पर मौजूद है। न्यूजीलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर एक भी सांप मौजूद नहीं है।

जंगली जानवरों की कोई कमी नहीं-

यही कारण है कि इसे सांप रहित देश भी कहा गया है। इस द्वीप के देश में जंगली जानवरों की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही ऐसा भी नहीं है कि इस देश में सरीसृप मौजूद नहीं है ना ही इस देश में जंगली जानवरों की कमी है। इसके बावजूद भी यहां एक भी सांप नहीं है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के आसपास समुद्र में बहुत से प्रकार के सांप देखने को मिलते हैं।

एक भी सांप नहीं-

फिर भी अभी तक यहां जमीन पर एक भी सांप दिखाई नहीं दिया है, जिससे ऐसा लगने लगा है कि वह पृथ्वी से कहीं गायब तो नहीं हो रहे हैं। धरती पर सांपों की जितनी भी प्रजातियां हैं, उतनी ही उनके भोजन में विविधता देखने को मिलती है। ऐसे में उनका न्यूज़ीलैंड जैसे देश में ना पाया जाना है। सच में हैरान कर देने वाली बात है।

न्यूजीलैंड में सांपों पर बैन-

इसके साथ ही एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि वैसे तो बहुत से लोग सांपों को पालते हैं, इसके लिए वह अलग-अलग प्रजातियों को अन्य देशों से भी मंगवाते हैं तो सवाल यह उठता है कि अगर न्यज़ीलैंड में सांप नहीं है तो क्या वहां के लोग बाहर से भी सांप नहीं मंगवाते। इस सवाल का जवाब न्यूजीलैंड के कानून में हैं जी हां न्यूजीलैंड में सांपों को बैन किया गया है। इसी बैन के चलते वहां के लोग बाहर से भी किसी तरह के सांप को अपने देश में नहीं ला सकते हैं।

एक और ऐसा देश-

यह कानून इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहां सरकार और साथ ही वहां के लोगों का मानना है कि अगर वहां सांप आते हैं तो वह उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि एक और ऐसा देश है, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि आज यहां पर एक भी सांप मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है पहले के समय में इसे सांपो का देश कहा जाता था। लेकिन पैट्रिक नाम के एक संत ने पूरे देश के सापों को एक साथ घेर लिया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया था। इसलिए यहां आज एक भी सांप मौजूद नहीं है।

रामायण में श्रीलंका के दर्शाए सभी 52 स्थलो का ट्रेल प्रोजेक्ट उद्घाटन समारोह

श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर संतोष झा ने रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के टॉप अधिकारियों की मेजबानी की और उन तरीकों पर चर्चा की, जिनसे भारत श्रीलंका में रामायण ट्रेल के विकास का समर्थन कर सके. संतोष झा ने इंडिया हाउस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज और उनकी टीम से मुलाकात की. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार संस्था है. श्रीलंका में इंडियन हाई कमीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उच्चायुक्त संतोष झा ने इंडिया हाउस में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज और उनकी टीम की मेजबानी की. इसमें कहा गया कि इस दौरान उन तरीकों पर चर्चा की गई, जिनसे भारत श्रीलंका में रामायण ट्रेल के विकास, लोगों से लोगों तक जुड़ाव और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके. संतोष झा श्रीलंका में स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज द्वारा समर्थित रामायण ट्रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हुए. उच्चायोग ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि आज जिस तरह भारत-श्रीलंका की दोस्ती फल-फूल रही है, उसी तरह रामायण ट्रेल भी फले-फूले ! उच्चायुक्त श्रीलंका में रामायण ट्रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए, जिसका समर्थन स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने किया. इसके अलावा एनएसए सागला रत्नायका, क्रिकेट आइकन सनथ जयसूर्या और अन्य लोग मौजूद रहे. रामायण प्राचीन भारत के दो प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है और हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है. **श्रीलंका में रामायण ट्रेल पर 52 स्थल हैं।**

मटन-मछली पर भी भारी सब्जी! स्वाद के साथ सेहत के लिए भी लाभकारी, ताकत से भरपूर

कटहल विभिन्न लाभकारी गुणों से भरपूर है. आमतौर पर यह गर्मियों के सीजन में आसानी से मिल जाता है. इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के साथ ही ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. आपने जायके के लिए कटहल की सब्जी का स्वाद जरूर लिया होगा. लेकिन क्या आप इसके फायदे के बारे में जानते हैं. कटहल हमारे शरीर के लिए काफी लाभकारी है. कटहल एक मौसमी सब्जी है जो कि आमतौर पर गर्मियों के सीजन में मिलती है. इसमें ऐसे कई औषधि गुण होते हैं जो कि न केवल सब्जी के स्वाद को बढ़ाते हैं. बल्कि हमारे शरीर में न्यूट्रिशस भी पहुंचाते हैं. लिहाजा हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी माने जाते हैं. कटहल का हम विभिन्न व्यंजनों में प्रयोग करते हैं. वहीं इसमें विटामिन, मिनरल, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसके साथ ही इसमें राइबोफ्लेविन, थियामिन, पोटेशियम कार्बन, मैग्नीशियम, मैंगनीज और फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते है. कटहल सब्जी के साथ इसके फल को पकाकर भी खाना लाभकारी होता है. कैंसर का खतरा भी करता है कम जिस प्रकार कटहल में विभिन्न प्रकार के फाइटो न्यूट्रिएंटस पाए जाते हैं. इसमें एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कैंसर और एंटी अल्सर के साथ ही एंटी एजिंग तत्व भी मौजूद रहते हैं. जो कि हमारे शरीर में कैंसर की सेल्स को बनने से रोकने के साथ ही हमारे पेट के अल्सर में भी बहुत ही लाभकारी होता है. कटहल के सेवन का तरीका वैसे तो कटहल के अंदर अलग-अलग में पोषक तत्व होते हैं. जो कि हमारी पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं. ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में सहायक होते हैं. इसके साथ ही दिल की समस्याओं को भी दूर करने में लाभकारी माना जाता है. अगर स्किन की समस्या है तो उसमें भी यह फायदेमंद है. कटहल के नुकसान कटहल का बहुत अधिक सेवन किया तो अपच, दस्त के साथ ही एसिडिटी की भी समस्या बढ़ जाती है. वहीं अगर आपको दस्त और स्किन एलर्जी है तो इसका सेवन करने से परहेज करना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को खून से जुड़ी कोई परेशानी है तो कटहल का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है.

सड़क सुरक्षा को कायम रखना - भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए एक मौलिक अधिकार

ऐसे देश में जहां प्रत्येक नागरिक बिना किसी डर या जोखिम के सड़कों पर चलने का हकदार है, सड़क सुरक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में उभरती है। जैसे-जैसे प्रगति की गति तेज़ होती है, सड़कों पर जीवन की सुरक्षा की आवश्यकता अनिवार्य हो जाती है। इस अनुसरण में, हमें निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए:

सुरक्षित बुनियादी ढांचे का अधिकार: प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए डिज़ाइन और रखरखाव की जाने वाली सड़क बुनियादी ढांचे का अधिकार है। इसमें अच्छी तरह से चिह्नित लेन, स्पष्ट संकेत, सुरक्षित पैदल यात्री क्रॉसिंग और खतरों से मुक्त उचित रूप से बनाए रखी गई सड़कें शामिल हैं।

सुरक्षित वाहनों का अधिकार: नागरिकों को ऐसे वाहनों तक पहुंचने का अधिकार है जो कड़े सुरक्षा मानकों को पूरा करते हैं, जिससे टकराव की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसमें कठोर सुरक्षा परीक्षण और सभी के लिए किफायती, सुरक्षित परिवहन विकल्पों की उपलब्धता शामिल है।

शिक्षा और जागरूकता का अधिकार: प्रत्येक नागरिक को सड़क सुरक्षा पर व्यापक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम का अधिकार है। इसमें कम उम्र से ही सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं, पैदल यात्रियों की सुरक्षा और विचलित या बिगड़ा हुआ ड्राइविंग के खतरों को सिखाना शामिल है।

कानूनों को लागू करने का अधिकार: नागरिकों को सड़कों पर व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करने की उम्मीद करने का अधिकार है। इसमें अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड के साथ तेज गति से गाड़ी चलाने, नशे में गाड़ी चलाने और लापरवाह व्यवहार पर रोक लगाने जैसे उपाय शामिल हैं।

आपातकालीन प्रतिक्रिया का अधिकार: प्रत्येक नागरिक को सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित और प्रभावी आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं का अधिकार है। इसमें जीवन की हानि को कम करने और चोटों को कम करने के लिए त्वरित चिकित्सा सहायता, बचाव अभियान और दुर्घटना के बाद की देखभाल शामिल है।

समावेशी डिज़ाइन का अधिकार: विकलांग नागरिकों को सड़क के बुनियादी ढांचे और परिवहन प्रणालियों का अधिकार है जो समावेशी और सुलभ हैं। इसमें शारीरिक क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों, वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को डिजाइन करना शामिल है।

वकालत और भागीदारी का अधिकार: प्रत्येक नागरिक को सड़क सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से की जाने वाली पहल की वकालत करने और उसमें भाग लेने का अधिकार है। इसमें समुदाय-आधारित कार्यक्रमों में शामिल होना, नीतिगत बदलावों का समर्थन करना और सुरक्षित सड़कें सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को जवाबदेह बनाना शामिल है।

इन मौलिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए, भारत न केवल अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करता है बल्कि सतत विकास और प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। सामूहिक प्रयास, अटूट प्रतिबद्धता और सुरक्षा के साझा दृष्टिकोण के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां हर यात्रा सुरक्षा और मन की शांति से चिह्नित होगी। आइए हम सभी के लिए सड़क सुरक्षा को वास्तविकता बनाने के लिए मिलकर काम करें।

डॉ अंकुर शरण

वंदे भारत के 3 वर्जन, पहला- चेयर कार, दूसरा- स्लीपर और तीसरा' जानें क्या है पूरा प्लान

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे की क्षमता में पिछले 10 वर्षों में जबरदस्त परिवर्तन देखा गया है. अगले पांच वर्षों में इसका और तेजी से विस्तार किया जाएगा. जैसे कि पिछले 10 सालों के दौरान वंदे भारत स्लीपर, चेयर कार और मेट्रो ट्रेनों से लेकर यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक सुपर ऐप तक के निर्माण पर तेजी से काम हो रहा है. इस काम में और तेजी लाने का प्रयास है. भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में भारतीय रेलवे को और मजबूत करने के लिए अपना पूरा खाका बहुत स्पष्ट रूप से रखा है. अश्विनी वैष्णव ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि अगले पांच वर्षों में रेलवे की क्षमता का बहुत तेजी से विस्तार किया जाएगा." अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन के तीन वर्जन हैं- स्लीपर, चेयर कार और मेट्रो. वंदे भारत की चेयर कार संस्करण पहले से ही पटरियों पर है, वंदे भारत स्लीपर की पहली कार बॉडी तैयार है और पहली स्लीपर ट्रेन अगले पांच-छह महीनों में तैयार हो सकती है. इन तीन वंदे भारत ट्रेनों द्वारा यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं और यात्रा अनुभव प्रदान किए जा रहे हैं. चौथी अमृत भारत ट्रेन का निकट भविष्य में बड़ी संख्या में निर्माण किया जाएगा ताकि कोई भी यात्री लंबी दूरी की यात्रा आराम से कर सके।

किसानों का विरोध प्रदर्शन, आत्महत्या कर चुके लोगों के कंकाल लेकर दिल्ली पहुंचे किसान

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: तमिलनाडु के करीब 200 किसान फसल की कीमतों और नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी जंतर मंतर पर आए हैं. प्रदर्शनकारी उन किसानों की खोपड़ी और हड्डियों के साथ आए हैं, जिन्होंने पिछले सालों में आत्महत्या की है. नेशनल साउथ इंडियन रिवर इंटरलिंकिंग फार्मर्स एसोसिएशन, तमिलनाडु के अध्यक्ष अय्याकन्नू ने आज तक से बात करते हुए कहा, '2019 के चुनावों के दौरान पीएम ने घोषणा की थी कि मैं फसलों का दोगुना मुनाफा दूंगा और नदियों को आपस में जोड़ूंगा.'

किसानों ने कहा कि पहले उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई और पुलिस ने उन्हें रोक दिया. किसान नेता ने कहा, 'हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन पुलिस ने रोक दिया.' बाद में उन्हें अदालत से प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई. किसानों के अनुसार केंद्र सरकार ने कृषि में दोगुनी आय का वादा किया था, लेकिन फसलों की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं. किसानों ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनेगी तो वे पीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी जाएंगे. अय्याकन्नू ने कहा, 'अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम वाराणसी जाकर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे.' किसानों ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन किया है. उन्होंने कहा कि हम पीएम के खिलाफ नहीं हैं या हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. हम सिर्फ उनकी मदद चाहते हैं।

पर्यावरण पाठशाला : "कूड़े का पहाड़ और प्लास्टिक की नहर - दिल्ली एनसीआर में पर्यावरणीय तबाही का मंडराता ख़तरा"

पर्यावरणीय तबाही का मंडराता ख़तरा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) पर छाया हुआ है, क्योंकि करोना के काले बादल आसमान पर मंडरा रहे हैं, और यमुना नदी का एक समय का प्राचीन पानी अब प्रदूषण से भरा हुआ है। हाल की रिपोर्टें स्थायी जीवन के प्रति लापरवाही और उदासीनता की एक गंभीर तस्वीर पेश करती हैं, जिसमें कचरा डंपिंग साइटें नरक जैसी दिखती हैं और महत्वपूर्ण जलमार्ग प्लास्टिक कचरे से भरे हुए हैं।

फ़रीदाबाद में, एक नहर पर्यावरणीय प्रबंधन को प्राथमिकता देने में हमारी सामूहिक विफलता का प्रमाण है। प्लास्टिक के मलबे से दबा हुआ, कभी बहने वाला इसका पानी अब स्थिर हो गया है, हमारी उपेक्षा के बोझ से दम तोड़ रहा है। मृत जानवर हमारे कार्यों के परिणामों की भयावह याद दिलाते हैं, क्योंकि प्रदूषण और उपेक्षा के दबाव में पारिस्थितिकी तंत्र ढह जाता है।

इस संकट के मूल में हमारे कार्यों और उनके परिणामों के बीच एक बुनियादी अंतर है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुविधा अक्सर विवेक पर भारी पड़ती है, जहां कचरे को अंधाधुंध डंप करने की सुविधा उचित निपटान की जिम्मेदारी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे-जैसे पर्यावरणीय क्षति बढ़ती जा रही है, हम अब अपने कार्यों के परिणामों से आंखें मूंदने का जोखिम नहीं उठा सकते।

परिवर्तन का समय अब है। हमें स्थिरता की संस्कृति की ओर बढ़ना चाहिए, जहां प्रत्येक व्यक्ति हमारे ग्रह के भविष्य को आकार देने में अपनी भूमिका को स्वीकार करता है। इसकी शुरुआत शिक्षा और जागरूकता से होती है, जो पृथ्वी पर सभी जीवन के अंतर्संबंध की गहरी समझ को बढ़ावा देती है।

लेकिन केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है. हमें कड़े नियम भी बनाने चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू करना चाहिए, उद्योगों और व्यक्तियों को उनके पर्यावरणीय पदचिह्न के लिए समान रूप से जिम्मेदार बनाना चाहिए। इसमें उचित अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे शहरों का कोई भी कोना हमारे कूड़े का डंपिंग ग्राउंड न बने।

इसके अलावा, हमें स्वच्छ, हरित भविष्य के लिए अपनी लड़ाई में सहयोगी के रूप में नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों तक, ढेर सारे समाधान मौजूद हैं जिनकी खोज की जा रही है। नवप्रवर्तन की शक्ति का उपयोग करके, हम न केवल पहले से हो चुके नुकसान को कम कर सकते हैं, बल्कि अधिक टिकाऊ कल के लिए मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं।

फिर भी, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की सामूहिक भावना विकसित करनी चाहिए। हम केवल इस ग्रह के निवासी नहीं हैं; हम इसके संरक्षक हैं, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी सुंदरता और विविधता को संरक्षित करने का काम सौंपा गया है। केवल एक साथ मिलकर, हाथ में हाथ डालकर काम करके ही हम आगे आने वाली चुनौतियों पर काबू पाने की उम्मीद कर सकते हैं।

करोना के काले बादल बड़े पैमाने पर मंडरा सकते हैं, और यमुना का पानी काला और प्रदूषित हो सकता है, लेकिन रास्ता बदलने में देर नहीं हुई है। आइए, स्वच्छ, हरित और अधिक टिकाऊ दिल्ली एनसीआर के लिए कार्रवाई के आह्वान को अपनाते हुए, हमारे सामने मौजूद चुनौती का सामना करें। हमारा ग्रह और आने वाली पीढ़ियाँ इस पर निर्भर हैं।

-अंकुर

indiangreenbuddy@gmail.com

दिल्ली में आंधी-बारिश से आफत, चार मंजिला घर के छत की दीवार पड़ोसी के मकान पर गिरी; छह नाबालिग सहित आठ घायल

परिवहन विशेष न्यूज

खिड़की एक्सटेंशन में मंगलवार शाम को आंधी व बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिर गई। इसके नीचे दबने से छह नाबालिग सहित आठ लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। शाम करीब छह बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में एक मकान की दीवार गिर गई है।

नई दिल्ली। मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में मंगलवार शाम को आंधी व बारिश की वजह से एक मकान की दीवार गिर गई। इसके नीचे दबने से छह नाबालिग सहित आठ लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर है।

दक्षिणी जिला पुलिस उपायुक्त अंकित चौहान ने बताया कि शाम करीब छह बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि मालवीय नगर के खिड़की एक्सटेंशन में एक मकान की दीवार गिर गई है। इसके नीचे कई लोग दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस को तुरंत मौके पर भेजा गया। तब तक सभी को मलबे के नीचे से निकालकर नजदीक के अस्पताल भेज दिया गया था।

चौथी मंजिल पर बाउंड्री की गिरी दीवार

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि खिड़की एक्सटेंशन में चार मंजिला मकान बना हुआ है। मकान की सबसे ऊपर की मंजिल पर चारों तरफ से करीब चार इंच दीवार की बाउंड्री कर रखी है। शाम को अचानक तेज आंधी और बारिश की वजह से दीवार का एक हिस्सा गिर गया।

इससे बिल्डिंग से सटे दूसरे मकान की छत पर कुछ बच्चे व उनके परिजन बैठे थे। दीवार का मलबा उनके ऊपर गिर गया। इससे उनके सिर व हाथ में चोट आई। सभी को उनके स्वजन ने अस्पताल में भर्ती कराया। गनीमत रही कि हादसे में उन्हें मामूली चोट आई।

चार घायलों को दी छुट्टी

चार घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बाकी का उपचार भी किया जा रहा है। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मकान किसी कासिम के नाम पर है। वह पुलिस को मौके पर नहीं मिला। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मामले में शिकायत आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

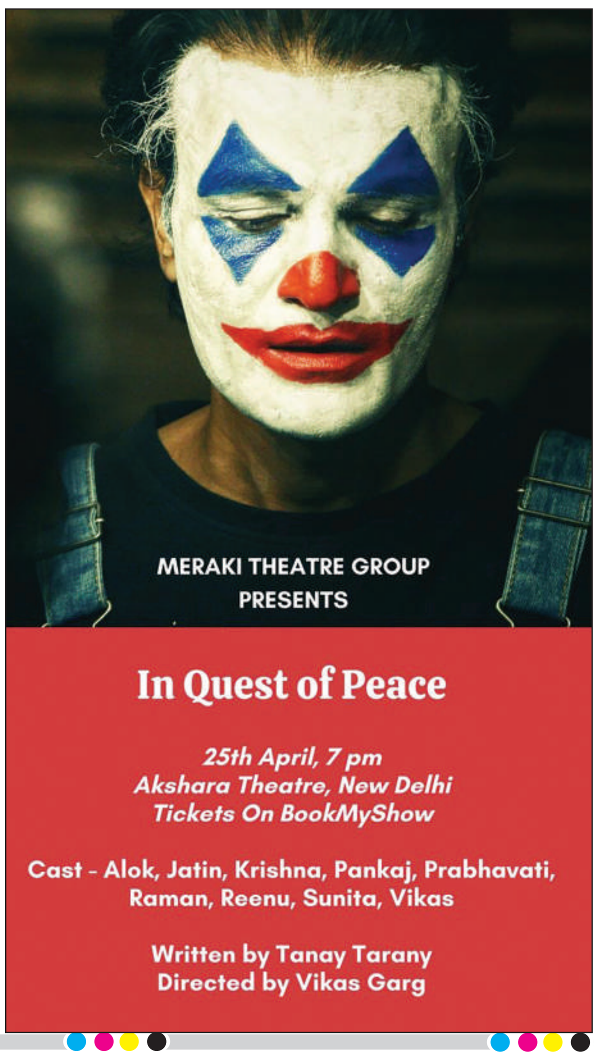

एसीएमओ के निरीक्षण में सीएचसी बम्हैटा में लगा मिला ताला

यह सीएचसी पांच लाख से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध किये जाने के लिए पिछले वर्ष ही खोली गई है। इसका उद्घाटन उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक द्वारा किया गया था। केंद्र पर चार चिकित्सक तैनात हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा.शालिनी सुमन एसीएमओ को रास्ते में मिलीं। इससे पहले भी सीएमओसीडीओ और एसडीएम स्तर से सीएचसी का निरीक्षण किया जा चुका है।

गाजियाबाद। गाजियाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों का बुरा हाल है। मंगलवार को सीएमओ के निर्देश पर एसीएमओ डॉ. अमित विक्रम सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बम्हैटा का सुबह को साढ़े आठ बजे आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर ताला लगा मिला, जबकि सीएचसी 24 घंटे चालू रहती है। इमरजेंसी सेवाओं को अनिवार्य रूप से संचालित किया जाता है। एसीएमओ ने निरीक्षण रिपोर्ट सीएमओ, डीएम और महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को भेज दी है।8 रिपोर्ट में अनुपस्थित चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई है। यह सीएचसी पांच लाख से अधिक लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध किये जाने के लिए पिछले वर्ष ही खोली गई है। इसका उद्घाटन उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक द्वारा किया गया था। केंद्र पर चार चिकित्सक तैनात हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डा.शालिनी सुमन एसीएमओ को रास्ते में मिलीं। इससे पहले भी सीएमओ,सीडीओ और एसडीएम स्तर से सीएचसी का निरीक्षण किया जा चुका है।

गौतमबुद्धनगर में 10 हजार जवान संभालेंगे चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा, 26 अप्रैल को होगा मतदान

परिवहन विशेष न्यूज

गौतमबुद्धनगर में 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। जिले में दस हजार जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। हर सुपरजोन में सेक्टर मजिस्ट्रेट व डीसीपी की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर बूथ पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्स ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। जिले में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था को पुख्ता करने में जुटी हुई है।

ग्रेटर नोएडा। जिले में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान जिले में दस हजार जवान सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। इसमें पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री के जवान भी शामिल रहेंगे। पूरे जिले को सात सुपर जोन व 120 सेक्टर में तब्दील किया जाएगा।

हर सुपरजोन में सेक्टर मजिस्ट्रेट व डीसीपी की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर बूथ पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति मतदान को प्रभावित न कर सके इसके लिए हर बूथ पर पैरामिलिट्री के जवान की तैनाती भी सुनिश्चित की जा रही है।

हर बूथ पर लगाया गया सीसीटीवी कैमरा

सुबह पांच बजे से पुलिसकर्मी बूथ पर तैनात हो जाएंगे। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसकी निगरानी जिले के कंट्रोल रूम के अलावा लखनऊ से भी की जाएगी।

दरअसल, गौतमबुद्धनगर में चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ न कर सकें, इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में पुलिस लगातार पैदल गश्त कर रही है।

देहात क्षेत्र में पुलिस बैठक कर लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी व्यक्ति के बहकावे में न आएं और निर्भीक होकर मतदान करें। पैरामिलिट्री फोर्स ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। जिले में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस व्यवस्था को पुख्ता करने में जुटी हुई है।

13 आइपीएस पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी

पुलिस का दावा है कि व्यवस्था ऐसी होगी कि कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगा। 13 आइपीएस सहित कुल 35 से अधिक राजपत्रित अधिकारियों के कंधे पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी होगी। संसाधनों से लैस पुलिस सीसीटीवी की मदद लेकर असामाजिक तत्वों को पकड़ने का प्रयास करेगी।

जिन दस हजार जवानों की ड्यूटी चुनाव में लगाई गई है उनमें कुछ जिले में तैनात पुलिसकर्मी होंगे जबकि कुछ अन्य जनपदों से चुनाव से ठीक पहले जिले में आएंगे। देहात के क्रिटकल बूथों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात किया जाएगा। शहरी बूथ पर भी पुलिस पर्याप्त संख्या में नजर आएगी।

एसीपी के कंधे पर भी जिम्मेदारी

जिले के बीस-बीस गांव से अधिक की जिम्मेदारी एक-एक एसीपी को सौंपी गई है। एसीपी ने गांव में पुलिस फोर्स के साथ जाकर लोगों से बातचीत शुरू कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि यदि उनको कोई भी व्यक्ति चुनाव के दौरान डराता धमकाता है तो तुरंत सूचना पुलिस को दें। पुलिस ने लोगों से कहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी जरूर लें।

गाजियाबाद में 26 अप्रैल को मतदान और जलपान, बाकी स्कूल, कॉलेज में सार्वजनिक अवकाश

लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। मतदाताओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर श्रम विभाग ने सार्वजनिक अवकाश और सामान्य अवकाश घोषित किया है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों को मतदान के लिए अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बागपत लोकसभा सीट पर आने वाली जिले के मोदीनगर विधान क्षेत्र में भी स्कूल कॉलेज बाजार आदि बंद रहेंगे।

गाजियाबाद। लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए संसदीय क्षेत्र तहत हापुड़ जिले की धौलाना विधानसभा क्षेत्र में भी मतदाताओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर श्रम विभाग ने सार्वजनिक अवकाश और सामान्य अवकाश घोषित किया है।

उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने बताया कि 26 अप्रैल को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। दूसरे चरण में शुक्रवार को मतदान दिवस पर जिले भर के स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद रहेगा

लोकसभा क्षेत्र के गाजियाबाद, साहिबाबाद, लोनी, मुरादनगर और हापुड़ की धौलाना विधानसभा क्षेत्र में भी अवकाश रहेगा। इसके अलावा बागपत लोकसभा सीट पर आने वाली जिले के मोदीनगर विधान क्षेत्र में भी स्कूल, कॉलेज, बाजार आदि बंद रहेंगे।

क्रेन से खींचकर कार चुरा ले गए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

पीड़ित को कई दिन परेशान करने के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है। मामला कोतवाली क्षेत्र की रेलवे रोड का है। इस बारे में राहगीर ने बताया कि एक कार देर रात करीब तीन बजे क्रेन खींचकर ले जा रही थी। पीड़ित ने इसके बाद पुलिस के चक्कर लगाने शुरू किए। पुलिसकर्मियों ने सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें क्रेन कार ले जाती हुई दिखाई दी है।

गाजियाबाद। कोतवाली क्षेत्र में चोर रेलवे रोड पर खड़ी कार को क्रेन से खींचकर चुराकर ले गए। पीड़ित को कई दिन परेशान करने के बाद पुलिस ने मामले में केस दर्ज किया है।

जीटी रोड पर रेलवे रोड के पास आर्यनगर निवासी संजय कुमार पानी एवं कोल्ड ड्रिंक की दुकान चलाते हैं। संजय के मुताबिक 31 मार्च की रात उन्होंने अपनी कार शिव मंदिर के पास खड़ी की थी। सुबह उन्हें मौके पर कार नहीं मिली।

पुलिसकर्मियों ने देखी सीसीटीवी फुटेज

उन्होंने काफी तलाश किया तो किसी राहगीर ने बताया कि एक कार देर रात करीब तीन बजे क्रेन खींचकर ले जा रही थी। पीड़ित ने इसके बाद पुलिस के चक्कर लगाने शुरू किए। कई चक्कर लगाने के बाद पुलिसकर्मियों ने सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें क्रेन कार ले जाती हुई दिखाई दी है। पीड़ित का कहना है कि चौधरी मोड़ चौकी पर उन्होंने कई बार संपर्क किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने व्यस्त होने का बहाना बनाकर टरका दिया। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने रविवार को उनकी शिकायत पर केस दर्ज किया है।

एसीपी कोतवाली प्रियाश्री पाल का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। क्रेन नंबर के आधार पर शीघ्र आरोपितों को पकड़ा जाएगा।

गैंगस्टर रवि काना और महिला मित्र काजल के थाईलैंड में गिरफ्तार होने की सूचना, भारत लाने की चल रही प्रक्रिया

सरिया व स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना व उसकी महिला मित्र काजल झा के थाईलैंड में गिरफ्तार होने की सूचना है। तकनीकी कारणों के चलते स्थानीय पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। हालांकि सूत्रों ने दावा किया है कि रवि को भारत लाने के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके खिलाफ लुक आउट व रेड कॉर्नर नोटिस जारी था।

ग्रेटर नोएडा। सरिया व स्क्रैप माफिया रवि नागर उर्फ रवि काना व उसकी महिला मित्र काजल झा के थाईलैंड में गिरफ्तार होने की सूचना है। तकनीकी कारणों के चलते स्थानीय पुलिस ने अभी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है।

हालांकि सूत्रों ने दावा किया है कि रवि को भारत लाने के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उसके खिलाफ लुक आउट व रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। वह मंगलवार को थाईलैंड एयरपोर्ट पर दुबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचा था, तभी रेड कॉर्नर नोटिस के तहत वहां की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है।

थाईलैंड की पुलिस ने दी मौखिक सूचना

वर्तमान में रवि व काजल दोनों पर 25-25 हजार का इनाम है। सूत्रों ने दावा किया है कि थाईलैंड की पुलिस ने मौखिक सूचना तो दी है, लेकिन मेल पर इसकी जानकारी अभी कमिश्नरेट पुलिस को नहीं दी है।

पुलिस को शुरू से था थाइलैंड में होने का शक

दरअसल, सरिया व स्क्रैप माफिया रवि के खिलाफ जनवरी 2024 में लुक आउट व रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इन नोटिस के साथ पुलिस ने रवि पर दर्ज केस की जानकारी थाईलैंड पुलिस से साझा की थी। पुलिस को शुरू से शक था कि रवि थाईलैंड में है। मंगलवार को थाईलैंड की पुलिस ने रवि के एयरपोर्ट पहुंचते ही उसको हिरासत में ले लिया है।

रवि काना गिरोह के 14 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हुए

रवि काना गिरोह के 14 आरोपितों को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि रवि व काजल अब पकड़े गए है। रवि के खिलाफ पुलिस गैंगस्टर एक्ट व सामूहिक दुष्कर्म के केस में पांच सौ से अधिक पन्ने की चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। उसकी 150 करोड़ से अधिक की संपत्ति अब तक पुलिस जब्त कर चुकी है।

पिछले वर्ष हटी थी सुरक्षा

रवि को पूर्व में पुलिस सुरक्षा मिली हुई थी। रवि के भाई हरेंद्र की हत्या में वह गवाह था। हत्या के मामले में सुंदर को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। गवाही पूरी होने व रवि की अवैध गतिविधियों का पता चलने पर जून 2023 में उसकी पुलिस सुरक्षा हटा ली गई थी। आरोप यह भी है कि रवि ने पुलिस सुरक्षा का दुरुपयोग किया। पुलिस सुरक्षा में रहकर वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा।

जबरन ठेके लेने का आरोप

रवि पर बीटा दो कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट व सेक्टर-39 कोतवाली में सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज है। आरोप है कि रवि गिरोह बनाकर फैक्ट्रियों में जबरन स्क्रैप का ठेका लेता था। ठेका लेने के लिए वह फैक्ट्री प्रबंधन को धमकाता था। इससे वह काली कमाई करता था, जिसका बंदरबांट कई सफेदपोश लोगों में होती थी।

रवि की डायरी में मिलें हैं कई नेताओं के नाम

पुलिस ने रवि काना के घर से कुछ दिन पहले एक डायरी बरामद की थी। डायरी में उन नेताओं के नाम लिखें हुए हैं, जिन्हें वह काली कमाई में से हिस्सा देता था। पुलिस ने इसकी जानकारी प्रदेश सरकार को सांझा की थी। डायरी में यह भी लिखा था कि किस नेता को महीने में कितना पैसा काली कमाई में से दिया जाता था।

मतदाता की बेरुखी लोकतंत्र के लिए नहीं हैं अच्छे संकेत

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले मतदाताओं को किसी भी हालत में देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं कहा जा सकता। आज चुनाव आयोग ने जहां अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागृत किया हैं वहीं पारदर्शी और सहज मतदान व्यवस्था सुनिश्चित की है।

18 वीं लोकसभा के लिए पहले चरण की 102 सीटों के लिए मतदान के प्रति मतदाताओं की उदासीनता ने निराश ही किया है। आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी मतदान प्रतिशत बढ़ने के स्थान पर कम होना निश्चित रुप से किसी भी रुप में लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। चुनाव आयोग के लाख प्रयासों के बावजूद मतदान प्रतिशत कम होना निश्चित रुप से सोचने को मजबूर कर देता है। चुनाव आयोग से पहले चरण के मतदान के प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाये तो साफ हो जाता है कि 2019 की तुलना में दो प्रतिशत तक मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। हांलाकि त्रिपुरा और सिक्किम में मतदान का आंकड़ा 80 प्रतिशत को छूने में सफल रहा है पर वहां भी 2019 की तुलना में कम है। त्रिपुरा में 2019 के 81.9 प्रतिशत की तुलना में 81.5 प्रतिशत और सिक्किम में 84.8 प्रतिशत की तुलना में 80 प्रतिषत मतदान रहा है। पहले चरण के चुनावों में मतदान का सबसे कम प्रतिशत बिहार का रहा है जहां मतदान का आंकड़ा 50 प्रतिषत को भी छू नहीं पाया है। छत्तीसगढ़ में अवश्य 2019 की तुलना में एक प्रतिशत से कुछ अधिक मतदान रहा है। जहां तक राजस्थान का प्रश्न है 12 सीटों पर हुए मतदान में मतदान प्रतिषत में 6 फीसदी की गिरावट रही हैं। सभी सीटों पर मतदान का प्रतिषत 2019 की तुलना में कम रहे हैं। हांलाकि चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ें आरंभिक सूचना के आधार पर है पर इनमें कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। मजे की बात यह है कि पहले चरण में लोकसभा की 543 सीटों में से 20 प्रतिशत से कुछ कम 102 सीटों पर मतदान हो चुका हैं। यदि मतदाताओं का अगले चार चरणों के मतदान में भी यही रुख रहता है तो यह चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों, लोकतांत्रिक व्यवस्था, गैरसरकारी संगठनों सहित सभी के लिए चिंतनीय हो जाता है।

मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले मतदाताओं को किसी भी हालत में देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं कहा जा सकता। आज चुनाव आयोग ने जहां अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागृत किया हैं वहीं पारदर्शी और सहज मतदान व्यवस्था सुनिश्चित की है। आज मतदाताओं को किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक मतदान केन्द्र पर एक सीमा तक ही मतदाता होने के साथ ही मतदान केन्द्र पर सभी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। अब तो मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता क्रमांक से लेकर मतदान केन्द्र तक की जानकारी का समावेश करते हुए परची उपलब्ध कराई जाती है। सीनियर सिटिजन और मतदान केन्द्र तक जाने में अक्षम मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा दी गई है। मतदाताओं को जागृत करने के लिए प्रचार के सभी माध्यम यहां तक कि सोशियल मीडिया का उपयोग किया जाने लगा है। मतदान को निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए संपूर्ण व्यवस्था चाक चोबंद की जाती है। राजनीतिक दलों और उम्मीद्वारों की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाती है। यहां तक कि उम्मीद्वार से संबंधित जानकारी साझा की जाती है। संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर विशेष व्यवस्था होती है। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही मतदान केन्द्र पर सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा यह नहीं भूलना चाहिए कि साक्षरता और लोगों में जागरुकता आई है। चुनाव आयोग के अलग अलग ऑब्जरवर द्वारा पूरी व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाती है ताकि राजनीतिक दलों या उम्मीद्वारों द्वारा मतदाताओं को किसी भी गलत तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सके। इस सबके बावजूद मतदान कम होना गंभीर हो जाता है।

लोकसभा के पहले चुनाव 1952 में 44.87 प्रतिशत मतदान रहा था जो सर्वाधिक 67.40 प्रतिशत 2019 के 17 वीं लोकसभा के चुनाव में रहा। मतदान में उतार चढ़ाव तो देखा जाता रहा है पर चुनाव व्यवस्था के सरलीकरण, पारदर्शिता,

> “ मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले मतदाताओं को किसी भी हालत में देश का जिम्मेदार नागरिक नहीं कहा जा सकता। आज चुनाव आयोग ने जहां अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागृत किया हैं वहीं पारदर्शी और सहज मतदान व्यवस्था सुनिश्चित की है। आज मतदाताओं को किसी राजनीतिक दल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक मतदान केन्द्र पर एक सीमा तक ही मतदाता होने के साथ ही मतदान केन्द्र पर सभी तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। अब तो मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा मतदाता क्रमांक से लेकर मतदान केन्द्र तक की जानकारी का समावेश करते हुए परची उपलब्ध कराई जाती है।

निष्पक्ष चुनाव की चाकचोबंद व्यवस्था, ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में साक्षरता में बढ़ोतरी के बावजूद यदि मतदान प्रतिशत 90 के आंकड़ें को भी नहीं छूता है तो यह घोर निराशाजनक है। हांलाकि आजादी के बाद सर्वाधिक मतदान 1984 के 64.01 के आंकड़ें.को 2014 में पीछे छोड़ा गया पर 2019 के पहले चरण के मतदान से निराशा ही हाथ लगी है। आखिर शिक्षित मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के प्रति इतना गैरजिम्मेदार कैसे हो रहा है। सब कुछ को अलग कर दिया जाये तो भी इस बात से नहीं नकारा जा सकता कि देश के नागरिक का भी अपने देश के प्रति लोकतंत्र के प्रति दायित्व होता है। आखिर हम सरकार की आलोचना करने में तो पीछे नहीं रहते पर कभी हमने सोचा है क्या कि हम मताधिकार का उपयोग करने के अपने दायित्व को नहीं समझ पाते हैं। अपनी सरकार चुनने के अवसर पर हम हमारे दायित्व को कैसे भूल जाते हैं। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पीण भी अपने आप में गंभीर हो जाती है। भारत जैसे देश के आम नागरिकों द्वारा इस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाना किसी अपराध से कम नहीं माना जाना चाहिए।

हमें गर्व होता है कि हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। पर हमें उस समय नीचे देखने को भी मजबूर होना पड़ता है जब इतने बड़े लोकतंत्र के पर्व पर आमनागरिक अपने दायित्व को समझने और उसे पूरा करने की भूल कर बैठता है और मताधिकार का उपयोग नहीं कर व्यवस्था को ठेंगा बताने का प्रयास करते हैं। मेरा तो यहां तक मानना है कि नोटा का प्रयोग भी सही विकल्प नहीं है वहीं मतदान का बहिष्कार तो देशद्रोह से कम अपराध नहीं माना जाना चाहिए। चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार गैरसरकारी संगठनों और समाज के प्रबुद्ध जनों को सोचना होगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर अपनी आहुति देने के काम से मुहं मोड़ने वालों के प्रति कोई सख्त कदम जैसा प्रावधान होना ही चाहिए। कोई ना कोई ऐसा संदेश जाना चाहिए ताकि लोग मतदान के प्रति संवेदनशील हो और मतदान अवश्य करें। यह समूची व्यवस्था को ही सोचने को मजबूर कर देता है। आने वाले चार चरणों में होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदाता हिस्सा ले इसके लिए सभी स्तर पर समन्वित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

दुनियाभर में इस साल बिकने वाली हर पांच में से एक कार होगी इलेक्ट्रिक, जानें कितनी बढ़ी मांग

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के मुताबिक दुनियाभर में इलेक्ट्रिक कारों की मांग काफी तेजी से बढ़ रही है। संस्था की ओर से एक रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इस कारण दुनियाभर में ऑटो उद्योग में काफी सुधार भी होगा। रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री और कीमत पर और क्या जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत सहित दुनियाभर में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक इस साल दुनियाभर में जितनी कारों की बिक्री होगी, उसमें हर पांच में से एक कार इलेक्ट्रिक होगी। संस्था की ओर से इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को लेकर और क्या जानकारी दी गई है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

पांच में से एक इलेक्ट्रिक कार की होगी बिक्री

आईईए (अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी) के नए संस्करण के मुताबिक, इस साल दुनिया भर में बिकने वाली पांच में से एक से ज्यादा कारों के इलेक्ट्रिक होने की उम्मीद है। अगले दशक में बढ़ती मांग के कारण वैश्विक ऑटो उद्योग में सुधार होगा और सड़क परिवहन के लिए तेल की खपत में काफी कमी आएगी।

2024 में होगी 17 मिलियन की बिक्री

वार्षिक ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक ने मंगलवार को कहा। आउटलुक में पाया गया है कि वैश्विक इलेक्ट्रिक कार की बिक्री 2024 में मजबूत रहने वाली है, जो साल के अंत तक लगभग 17 मिलियन तक पहुंच जाएगी। पहली तिमाही में बिक्री 2023 की समान अवधि की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत बढ़ी। वैश्विक स्तर पर बेची गई इलेक्ट्रिक कारों की संख्या इस वर्ष के पहले तीन महीने लगभग 2020 में बेची गई संख्या के बराबर हैं।

चीन में होगी सबसे ज यादा बिक्री

साल 2024 के दौरान चीन में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री लगभग 10 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जो देश में सभी कारों की बिक्री का लगभग 45 प्रतिशत है। अमेरिका में, बेची जाने वाली लगभग नौ कारों में से एक के इलेक्ट्रिक होने का अनुमान है - जबकि यूरोप में, यात्री कारों की बिक्री के लिए आम तौर पर कमजोर दृष्टिकोण और कुछ देशों में सब्सिडी के चरणबद्ध होने के बावजूद, इलेक्ट्रिक कारें अभी भी लगभग एक का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं।

पिछले साल, वैश्विक इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 35 प्रतिशत बढ़कर लगभग 14 मिलियन हो गई। जबकि मांग मुख्य रूप से चीन, यूरोप और अमेरिका में केंद्रित रही, वियतनाम और थाईलैंड जैसे कुछ उभरते बाजारों में भी विकास में तेजी आई, जहां बेची गई सभी कारों में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी क्रमशः 15 प्रतिशत और 10 प्रतिशत थी।

कीमतों में आ सकती है कमी

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और उनकी बैटरियों की कीमत में गिरावट से आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण बदलाव आने की उम्मीद है। आउटलुक ने पाया कि नीति सेटिंग्स के तहत, विश्व स्तर पर 2035 तक इलेक्ट्रिक होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बीच, यदि देशों ने घोषणा की कि ऊर्जा और जलवायु संबंधी वादों को पूर्ण और समय पर पूरा किया जाता है, तो 2035 तक बेची जाने वाली तीन में से दो कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इस परिदृश्य में, इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से चलन बढ़ेगा। IEA के कार्यकारी निदेशक फतिह बिरोल ने कहा। ₹वैश्विक ईवी क्रांति कम होने के बजाय विकास के एक नए चरण के लिए तैयार होती दिख रही है। बैटरी निर्माण में निवेश की लहर से पता चलता है कि ईवी आपूर्ति श्रृंखला विस्तार के लिए वाहन निर्माताओं की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। परिणामस्वरूप, सड़कों पर ईवी की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

रिलाइंस समेत ये 7 कंपनियां लगाएंगी ACC बैटरी प्लांट, PLI स्कीम के तहत किया आवेदन

सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसे इन कंपनियों से 3620 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 10 गीगावाट क्षमता वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए आवेदन मिले हैं। सूची में शामिल अन्य बोलीदाताओं में एसीएमई क्लीनटेक साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड अन्वी पावर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड लुकास टीवीएस लिमिटेड और वारी एनर्जीज लिमिटेड शामिल हैं।

नई दिल्ली। रिलायंस और जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी सहित सात कंपनियों ने बैटरी मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के तहत आवेदन किया है। आइए, पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

इन कंपनियों ने किया आवेदन

सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसे इन कंपनियों से 3,620 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 10 गीगावाट क्षमता वाले संयंत्र स्थापित करने के लिए आवेदन मिले हैं। सूची में शामिल अन्य बोलीदाताओं में एसीएमई क्लीनटेक साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अमारा राजा एडवांस्ड सेल टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड, अन्वी पावर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, लुकास टीवीएस लिमिटेड और वारी एनर्जीज लिमिटेड शामिल हैं।

क्या है अब तक का अपडेट?

भारी उद्योग मंत्रालय की इस साल 24 जनवरी को जारी एक वैश्विक निविदा के जवाब में कुल 70 गीगावाट क्षमता वाले मैन्युफैक्चरिंग संयंत्रों के लिए बोलिया मिली हैं। मंत्रालय ने कहा, इस योजना को उद्योग से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली क्योंकि प्राप्त बोलियां 10 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से सात गुना अधिक थीं। मंत्रालय ने 10 गीगावाट एडवांस केमिकल सेल (ACC) विनिर्माण के लिए पीएलआई की फिर से बोली लगाने की घोषणा की थी। बोली से पहले बैठक 12 फरवरी को हुई थी। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल थी और तकनीकी बोलियां मंगलवार को खोली गईं।

होण्डा एमेज चाइल्ड सेफ्टी के मामले में जीरो, ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में मिली 2-स्टार रेटिंग

परिवहन विशेष न्यूज

GNCAP ने कहा कि फ्रंट इम्पैक्ट टेस्ट में बच्चे का सिर संपर्क में आया। इसमें तीन साल के बच्चे की छाती और गर्दन की खराब सुरक्षा भी दिखी। 1.5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभाव पड़ने पर इजेक्शन जोखिम का सामना करना पड़ता है। सेडान में सभी सीटों पर तीन पॉइंट बेल्ट जैसी सुरक्षा सुविधाओं का भी अभाव है।

नई दिल्ली। Honda Amaze सब-कॉम्पैक्ट सेडान को Global NCAP क्रैश टेस्ट में महज 2-स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। सेडान ने बाल यात्री सुरक्षा परीक्षण में खराब स्कोर किया, जिससे इसकी समग्र सुरक्षा रेटिंग प्रभावित हुई। आपको बता दें कि GNCAP ने इसी मॉडल को 5 साल पहले टेस्ट किया था, तब इसे 4 सितारे दिए गए थे।

Honda Amaze ने किया निराश

इस साल ग्लोबल एनसीएपी द्वारा टेस्ट की गई होंडा अमेज मॉडल में स्टैंडर्ड रूप से दो एयरबैग हैं। सेडान को वयस्क यात्री सुरक्षा के लिए दो स्टार और बच्चों की सुरक्षा के लिए शून्य स्टार प्राप्त हुई। क्रैश टेस्ट से यह निष्कर्ष निकला कि होंडा अमेज में बच्चों के लिए खराब सुरक्षा पैरामीटर थे।

बच्चों के लिए असुरक्षित

एजेंसी ने कहा कि फ्रंट इम्पैक्ट टेस्ट में बच्चे का सिर संपर्क में आया। इसमें तीन साल के बच्चे की छाती और गर्दन की खराब सुरक्षा भी दिखी। 1.5 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभाव पड़ने पर इजेक्शन जोखिम का सामना करना पड़ता है। सेडान में सभी सीटों पर तीन पॉइंट बेल्ट जैसी सुरक्षा सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बाल यात्री सुरक्षा परीक्षण में केवल एक स्टार रेटिंग मिली।

होंडा अमेज को वयस्क यात्री सुरक्षा परीक्षण में दो स्टार मिले। कम स्कोर मानक के रूप में कोई ईएससी सुविधा नहीं होने, वैकल्पिक साइड हेड सुरक्षा की कमी के साथ-साथ केवल ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर सुविधा के कारण था।

सेफ्टी फीचर्स

दो एयरबैग और सीट बेल्ट रिमाइंडर के अलावा, होंडा अमेज स्टैंडर्ड रूप में ईबीडी के साथ एबीएस, रियर-व्यू कैमरा, चाइल्ड लॉक, चाइल्ड सीट के लिए एंकर पॉइंट, ओवरस्पीड वार्निंग और एंटी थेफ्ट इंजन इम्मोबिलाइजर जैसे फीचर्स के साथ आती है।

इंजन

होंडा अमेज भारत में जापानी ऑटो दिग्गज द्वारा बेची जाने वाली दो सेडान में से एक है, जिसमें सिटी और सिटी हाइब्रिड भी शामिल हैं। होंडा ने 2021 में अमेज का फेसलिफ्ट संस्करण लॉन्च किया और जल्द ही एक अद्यतन संस्करण लॉन्च करने की उम्मीद है। ये सेडान दो इंजन विकल्पों के साथ आती है। इसमें एक 1.2 पेट्रोल और एक 1.5 डीजल यूनिट शामिल है।

किआ इंडिया घरेलू बाजार में लॉन्च करेगी 3 नई इलेक्ट्रिक कार, लिस्ट में एक किफायती ईवी भी शामिल

Kia EV9 के प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल को पिछले साल वैश्विक बाजारों के लिए पेश किया गया था। इसकी अनुमानित लॉन्चिंग 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में होने की संभावना है। आईसीई किआ क्लैविस को विदेशों और भारत दोनों में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इस साल के अंत में विश्व प्रीमियर के लिए तैयार किया गया है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Kia India की ओर से इस कैलेंडर वर्ष के बचे हुए महीनों और 2025 की शुरुआत में कुल 3 नई Electric Cars लॉन्च की जाएंगी। इसमें दो फैमिली ईवी और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी शामिल है। आइए, इन तीनों के बारे में जान लेते हैं।

Kia EV9

Kia EV9 के प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल को पिछले साल वैश्विक बाजारों के लिए पेश किया गया था। इसकी अनुमानित लॉन्चिंग 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में होने की संभावना है। डब्ल्यूएलटीपी साइकिल में 541 किमी की ड्राइविंग रेंज का दावा करते हुए, ईवी9 विदेशों में सिंगल और डुअल-मोटर सेटअप दोनों के साथ आती है। भारतीय बाजार में भी इसे इन्हीं विकल्पों के साथ पेश किया जा सकता है।

Kia Clavis

आईसीई किआ क्लैविस को विदेशों और भारत दोनों में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है और इस साल के अंत में विश्व प्रीमियर के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद 2025 की शुरुआत में भारत सहित विभिन्न बाजारों में पेश किया जाएगा।

एक बार चार्ज करने पर ये एसयूवी 400 किमी से अधिक की क्लेम्ड रेंज दे सकती है। इंडियन मार्केट में यह टाटा पंच ईवी, एंट्री-लेवल और मिड-स्पेक नेक्सॉन ईवी और आगामी एमजी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी जैसी EVs को टक्कर देगी।

Kia Carens EV

साल 2025 की दूसरी छमाही में दक्षिण कोरियाई ऑटो दिग्गज द्वारा कैरेंस पर आधारित एक इलेक्ट्रिक एमपीवी पेश की जाएगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह क्लैविस ईवी के साथ बहुत सारे कंपोनेंट और बिट्स शेयर करेगी। हालांकि, इसको लेकर कोई खास जानकारी अब तक सामने नहीं आई है।

किआ केरेंस को ग्लोबल एनसीएपी क्रैश टेस्ट में मिली 5-स्टार रेटिंग; जानिए, बड़ो और बच्चों के लिए कितनी सुरक्षित

परिवहन विशेष न्यूज

Global NCAP में Kia Carens ने बाल सुरक्षा में पांच स्टार और वयस्क सुरक्षा में तीन स्टार हासिल किए हैं। जिस एमपीवी का परीक्षण किया वह फ्रंटल एयरबैग बेल्ट प्री-टेंशनर बेल्ट लोड लिमिटर्स साइड हेड कर्टेन एयरबैग और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट से लैस थी। रिजल्ट में कहा गया कि ड्राइवर और यात्री के सिर पर सामने का प्रभाव अच्छा था।

नई दिल्ली। Global NCAP ने Kia Carens का क्रैश टेस्ट रिजल्ट पब्लिश किया है। एमपीवी ने बाल सुरक्षा में पांच स्टार और वयस्क सुरक्षा में तीन स्टार हासिल किए हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कैरेंस का दो बार टेस्ट किया गया था, क्योंकि पहली बार में इसे वयस्क सुरक्षा में 0-स्टार मिले थे। मई 2023 से दिसंबर 2023 तक उत्पादित यूनिट्स को 0-स्टार मिले और उसके बाद उत्पादित यूनिट्स को 3 स्टार मिले हैं।

बड़ों और बच्चों के लिए इतनी सुरक्षित

Global NCAP ने जिस एमपीवी का परीक्षण किया वह फ्रंटल एयरबैग, बेल्ट प्री-टेंशनर, बेल्ट लोड लिमिटर्स, साइड हेड कर्टेन एयरबैग और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट से लैस थी। रिजल्ट में कहा गया कि ड्राइवर और यात्री के सिर पर सामने का प्रभाव अच्छा था। ड्राइवर की गर्दन को अपर्याप्त सुरक्षा मिली, जबकि यात्री की गर्दन अच्छी तरह से सुरक्षित थी।

साइड इफेक्ट के मामले में सिर, छाती, पेट और श्रोणि की सुरक्षा अच्छी थी। साइड पोल इम्पैक्ट नहीं किया गया। कार सभी संस्करणों में मानक के रूप में सभी बैठने की स्थिति में 3-पॉइंट बेल्ट प्रदान करती है।

Kia Carens की कीमत और वेरिएंट

किआ कैरेंस की कीमत वर्तमान में 10.52 लाख रुपये से 19.57 लाख रुपये के बीच है। दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं। इसे दस वेरिएंट में पेश किया जा रहा है। इसमें प्रीमियम, प्रीमियम (O), प्रेस्टीज, प्रेस्टीज (O), प्रेस्टीज प्लस, प्रेस्टीज प्लस (O), लग्जरी, लग्जरी (O), लग्जरी प्लस और एक्स-लाइन है। ग्राहक कैरेंस को 6-सीटर और 7-सीटर लेआउट में प्राप्त कर सकते हैं। तीन इंजन विकल्प हैं जिन्हें ग्राहक चुन सकते हैं।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता दवा क्षेत्र

डा. अश्विनी महाजन
कालेज एसोशिएट प्रोफेसर

'भारत सरकार को सजग रहते हुए एपीआई के क्षेत्र में चीन द्वारा की जा रही डंपिंग को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करने होंगे। अन्य रसायनों के क्षेत्र में भी यह बात लागू होती है'

लंबे समय से चीन पर निर्भर भारत के फार्मा क्षेत्र को अब कुछ राहत मिलने लगी है। कारण है आत्मनिर्भर भारत अभियान। गौरतलब है कि वर्ष 2000 तक भारत का दवा निर्माण क्षेत्र लगभग पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। दवा निर्माण में जो आवश्यक सामग्री इस्तेमाल होती है, उसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स, यानी एपीआई के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2000 तक दवा निर्माण के क्षेत्र में जिन एपीआई की आवश्यकता होती थी, वे अधिकांशतः भारत में ही निर्मित होते थे। देश में इनके निर्माताओं में आवश्यक प्रतिस्पर्धा भी थी, जिसके कारण दवा निर्माताओं को देश में एपीआई आसानी से और उचित कीमत पर उपलब्ध होते थे। इसके कारण देश का दवा उद्योग न केवल तेजी से आगे बढ़ रहा था, बल्कि दुनियाभर के लोगों को उचित कीमत पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने में भी समर्थ था। चीन ने एक षड्यंत्र के तहत भारत के एपीआई क्षेत्र को तबाह करना शुरू किया। चीन से आने वाले एपीआई को अत्यंत ही कम कीमतों पर भारत में भेजा जाने लगा। इसका असर यह हुआ कि भारत का एपीआई उद्योग प्रतिस्पर्धी नहीं रहा और हमारी एपीआई इकाइयां धीरे-धीरे करके बंद होने लगी। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है। एमोक्सीसाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक दवा, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट पेनीसिलिन-जी से व्युत्पन्न उत्पाद है। पेनीसिलिन-जी नाम की एपीआई भारत में पर्याप्त मात्रा में बनती थी और उसका अंतरराष्ट्रीय मूल्य लगभग 22 डॉलर प्रति किलोग्राम था। लेकिन चीन ने इस एपीआई की डंपिंग 9 डॉलर प्रति किलो से भी कम पर करनी शुरू कर दी।

इसके कारण भारत की इस एपीआई को बनाने वाली इकाइयां बंद हो गईं। उसके बाद चीन ने इसी एपीआई को पहले दोगुणा और फिर चार गुणा कीमत पर बेचना शुरू कर दिया। किसी विकल्प के अभाव में भारत की दवा कंपनियों को यह एपीआई, चीन द्वारा निर्धारित कीमत पर खरीदना जरूरी हो गया। लगभग यही स्थिति अन्य एपीआई की भी रही और कई एपीआई पूर्व से 10 से 20 गुणा कीमत पर भी बेचे जाने लगे। उदाहरण के लिए फॉलिक एसिड, जो विटामिन की दवा बनाने के काम आता है, की कीमत 13 गुणा से भी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। ऐसी स्थिति दवाओं के लगभग सभी एपीआई के संदर्भ में थी। कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि कोरोना काल में देखी गई और यह समझ में आना शुरू हुआ कि देश में एपीआई उद्योग की पुर्नस्थापना, केवल दवा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए या दवाओं की कीमतों को कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि देश में स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। यह सर्वविदित ही है कि चीन भारत के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध रखता है, इसलिए दवा के लिए आवश्यक सामग्री हेतु चीन पर निर्भर नहीं किया जा सकता।

एपीआई में आत्मनिर्भरता : मई 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी वस्तुओं, जिनका उत्पादन चीन और अन्य देशों द्वारा डंपिंग के कारण बाधित हो गया था, के उद्योगों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और विदेशों पर निर्भरता को समाप्त करने के उद्देश्य से, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। प्रारंभिक तौर पर इसके लिए जिन वस्तुओं की 13 श्रेणियों को चिन्हित किया गया, उनमें एपीआई भी शामिल थे। आत्मनिर्भरता हेतु अपनाए गए उपायों में से एक महत्वपूर्ण उपाय को उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) के रूप में जाना जाता है। गौरतलब है कि एपीआई क्षेत्र के लिए इस पीएलआई स्कीम में 41 उत्पाद शामिल किए गए, जिनमें मधुमेह, तपेदिक, स्टेरॉयड और एंटीबायोटिक्स के लिए दवाओं पर विशेष आग्रह रखा गया, और उसके लिए 20000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई। यह योजना 21 जुलाई 2020 को अधिसूचित की गई। हर्ष का विषय यह है कि यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लगी है और देश दवा उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन-जी, जिसका भारत में उत्पादन बंद हो गया था, जिसके कारण भारतीय उद्योगों से इस एपीआई की ऊंची कीमत वसूली जा रही थी, अब उसके उत्पादन हेतु ऑरविन्दो फार्मा लिमिटेड, टोरेंट फार्मास्यूटिकल आदि कंपनियों ने इसकी उत्पादन इकाइयां शुरू कर दी हैं और माना जा रहा है कि ऑरविन्दो फार्मा इस पेनिसिलिन-जी एपीआई का उत्पादन अप्रैल, 2024 में और टोरेंट जून-जुलाई 2024 में शुरू कर देगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का यह कहना है कि पीएलआई योजना और अन्य प्रयासों के कारण आज भारत अधिकांश एपीआई में आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है, जिसके कारण चीन पर निर्भरता कम हुई है। सितंबर 2023 तक पीएलआई स्कीम के तहत फार्मा कंपनियों को 4000 करोड़ रुपए और मेडिकल उपकरणों के लिए 2000 करोड़ रुपए के निवेश की अनुमति दी जा चुकी थी। इसके अलावा केन्द्र ने 3000 करोड़ रुपए की लागत से तीन बल्क (थोक) ड्रग पार्कों का निर्माण किया है।

घटने लगी हैं कीमतें : जैसे-जैसे एपीआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सुपरिणाम आने लगे हैं, वैसे-वैसे एपीआई की कीमतें भी घटने लगी हैं। फार्मा उद्योग के जानकार बता रहे हैं कि एपीआई की कीमतों में कोविड के समय से अभी तक 50 प्रतिशत की कमी आई है। इसमें से सबसे तेज गति से कमी पिछले दो महीनों में ही आई है। समझा जा सकता है कि कोविड काल में जब एपीआई के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयास शुरू हुए थे, अब वे फलीभूत होना शुरू हुए हैं। इकॉनोमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार बुखार की दवा पैरासिटामोल के एपीआई की कीमत जो कोविड काल में 900 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी, वह घटकर अब मात्र 250 रुपए प्रति किलो रह गई है। उसी प्रकार अस्थमा की दवा मॉनटैलूकास्ट सोडियम 45000 रुपए प्रति किलो से घटकर मात्र 28000 रुपए प्रति किलो रह गई है। एंटीबायोटिक मेरोपिनेम की एपीआई की कीमत 75000 रुपए प्रति किलो से घटकर 45000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। जानकारों का मानना है कि भारत में एपीआई उत्पादन में उठाव के चलते चीन का दवा (एपीआई और मध्यवर्ती उत्पाद समेत) कार्टेल पिछले छह महीने में टूट चुका है। शायद चीन को इस बात का आभास नहीं था कि भारत इतनी बड़ी तादाद में अपने दवा उद्योग को पुनर्जीवित करेगा। इसलिए उसने दुनिया भर के दवा उद्योग पर कब्जा जमाने की दृष्टि से अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर लिया था। अब ऊंची क्षमता के कारण चीन में एपीआई की आपूर्ति बहुत अधिक बढने के कारण कीमतों में कमी स्वाभाविक परिणाम है। गौरतलब है कि वर्ष 2021-22 में भारत द्वारा एपीआई के आयात में भारी वृद्धि हुई थी। वर्ष 2022-23 में भी इसमें कुछ वृद्धि देखी गई, लेकिन यह भी सच्चाई है कि जितनी थोक दवाओं का आयात वर्ष 2022-23 में हुआ, उससे लगभग 12300 करोड़ रुपए ज्यादा का निर्यात भारत से किया गया था।

अब चूंकि देश में भारी मात्रा में एपीआई का निर्माण होना शुरू हुआ है, एपीआई की घटती कीमतें उसका द्योतक हैं। लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उद्योग पीएलआई और सतर्क सरकारी नीतियों के कारण पुनर्जीवित हुए हैं, वे चीन द्वारा पुनः डंपिंग का शिकार न बन जाएं। पीएलआई स्कीम के तहत जिन उद्यमियों ने निवेश किया था, उनकी सबसे बड़ी शंका इसी बात को लेकर थी। भारत सरकार को सजग रहते हुए एपीआई के क्षेत्र में चीन द्वारा की जा रही डंपिंग को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास करने होंगे। यह बात सिर्फ एपीआई के मामले में ही नहीं, बल्कि अन्य रसायनों के क्षेत्र में भी लागू होती है। देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ खुफिया एजेंसी बनाने की आवश्यकता है ताकि अन्य देशों और उनके व्यवसायों द्वारा अनैतिक व्यापार व्यवहार की ऐसी किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।

संपादक की कलम से

कांग्रेस बनाम वाम मोर्चा

इतिहास में झांकें, तो कांग्रेस और खासकर सीपीएम दोनों दुश्मन भी रहे हैं और अवसरवादी मित्र भी रहे हैं। प्रसंगवश 2004 का उल्लेख करता हूं। कांग्रेस 145 सीटें जीत कर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा 138 सीटें ही जीत पाई थी। अर्थात जनादेश त्रिशंकु था, लिहाजा खिचड़ी सरकार ही बननी थी। उस लोकसभा में वामदलों के कुल 61 सांसद जीत कर आए थे। यह उस दौर में वाम की सबसे शानदार और बड़ी चुनावी जीत थी। तत्कालीन सीपीएम महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत ने मध्यस्थता की और कांग्रेस के नेतृत्व में, भाजपा-विरोधी दलों को जोड़ कर, यूपीए का गठन किया। सोनिया गांधी को उसका अध्यक्ष बनाया गया। डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए और सीपीएम सांसद सोमनाथ चटर्जी को स्पीकर का पद देकर वाममोर्चे को नवाजा गया। परोक्षरूप से तब केंद्र में वाममोर्चे की ही सरकार थी, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण निर्णय वाममोर्चे की सहमति से ही लिए जाते थे। कांग्रेस-वाम मित्रता की यह मिसाल कुछ और राज्यों में भी देखी गई, जहां दोनों ही दल विपक्षी गठबंधन के घटक थे। बंगाल, केरल, त्रिपुरा में वाम और कांग्रेस के बीच राजनीतिक शत्रुता बनी रही। केरल में तो दो ही मोर्चे सक्रिय रहे-वामदलों के नेतृत्व वाला फ्रंट तथा कांग्रेस नेतृत्व वाला यूनाइटेड फ्रंट। दोनों ही दल और मोर्चे मौजूदा विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के भी औपचारिक घटक हैं। यूपीए के आखिरी दौर में 'परमाणु करार' के मुद्दे पर मनमोहन सरकार से वाममोर्चे ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन तब मुलायम सिंह यादव की सपा और अन्य सांसदों के समर्थन से सरकार बची थी, लेकिन 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद जो भी विपक्षी गठबंधन बना, उसमें कांग्रेस और वामपंथी दोनों ही रहे। चूंकि अब लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, लिहाजा बंगाल, केरल और त्रिपुरा में दोनों ही पक्ष 'कट्टर प्रतिद्वंद्वी' की भूमिका में हैं।

केरल तो कांग्रेस के लिए चुनावी जीवन-रेखा है। 2019 के आम चुनाव में केरल में कांग्रेस नेतृत्व के यूनाइटेड फ्रंट ने 20 में से 19 सीटें जीत कर वाम को ध्वस्त कर दिया था। वाम का एकमात्र सांसद चुना गया था। हालांकि तमिलनाडु में वाममोर्चे के 2 सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के कुल 52 सांसद चुने गए थे, जिसमें केरल के 15 सांसद थे। इस बार वाममोर्चा यूं ही हथियार डालने को तैयार नहीं है, लिहाजा शब्दों और अलंकारों की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस और वाम एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को केरल में भी है। मुख्यमंत्री पी. विजयन ने फरवरी में ही कांग्रेस की तीखी आलोचना करते हुए चुनाव-प्रचार शुरू कर दिया था। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को 'एकाधिकारवादी' करार दिया। इस बार वायनाड की सीट पर राहुल गांधी का चुनाव भी आसान नहीं है। उनके खिलाफ सीपीआई की उम्मीदवार एनी राजा को उतारा गया है, जो सीपीआई महासचिव डी. राजा की पत्नी हैं और राजनीतिक तौर पर खूब सक्रिय रही हैं। वाम की पूरी सरकार उनके साथ प्रचार में व्यस्त है। केरल के नेता 'अमूल बेबी' नामक आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। क्या ऐसी ही चुनावी प्रतिद्वंद्विता को 'मैत्री-लड़ाई' कह सकते हैं? मुख्यमंत्री और राहुल गांधी एक-दूसरे पर बंदूक ताने सक्रिय हैं। वाममोर्चे की लोकप्रियता और स्वीकार्यता लगातार घट रही है। 2019 में सीपीएम ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन मात्र 3 ही सांसद जीत कर संसद तक पहुंच पाए। मात्र 2 फीसदी वोट मिले, जो सबसे कम रहा है। इस बार सीपीएम केरल में ही 15 सीटों पर लड़ रही है, जबकि बंगाल में 23 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। केरल 'मरो या मारो' की स्थिति में है। बेशक राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और वाम जिस तरह 'मैत्री-लड़ाई' की आड़ में चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या है? क्या उससे भाजपा को ही फायदा नहीं होगा? विपक्ष में वामपंथी और कांग्रेसी लड़ रहे हैं। चुनाव के निष्कर्ष का आकलन यहीं से किया जा सकता है।

राय

हिमाचल में लौटा पोलिथीन

बहुत वर्ष नहीं हुए जब तत्कालीन धूमल सरकार ने देश के पहले हिमालयी राज्य को पॉलिथीन मुक्त करने का बीड़ा उठाया और इस क्रांतिकारी कदम ने एक इतिहास लिख दिया, लेकिन इस व्यवस्था की बाद की सरकारें रक्षा न कर सकीं। पड़ोसी राज्यों की संगत में धीरे-धीरे लौट आया पॉलिथीन, क्योंकि पहाड़ के नियम तो सरकारें बदलते ही दफन हो जाते हैं। सर्वप्रथम जनता ही इनका शिकार करती है, जबकि प्रशासन को अब ऐसे कार्यों की फुसर्त ही कहां। आश्चर्य यह कि इस बीच स्वच्छता अभियान चले। गांव-गांव में सांसदों के नाम पर डस्टबिन लग गए, लेकिन कचरा और नजदीक तथा पॉलिथीन जमीन में धंस गया। हिमाचल ने पॉलिथीन यानी प्लास्टिक की बरसात देखनी हो, तो गांव से शहर तक की करतूत के हादसे किसी भी खड्ड, नदी या जलस्रोत के करीब देखिए। एक व्याख्या तो साल में राष्ट्रीय स्वच्छता का सर्वेक्षण कर देता है और ताज्जुब यह कि शिमला जैसा शहर भी हमने गंदगी की घुटनों तक पहुंचा दिया। आलम यह कि अश्विनी खड्ड के मुहाने तरस गए कि शिमला खुद को संभाल लेगा। यह हर शहर की दास्तान है, जहां वर्षों से कूड़े में प्लास्टिक लद रहा है। शहरों के साथ बहती खड्डें व नदियां बदनाम हैं और यही आगे चलकर हर बांध में तैरती जुबान है। हम जिसे सिल्ट कहते, उसके भीतर हर साल जमा हो रहा है हमारे फर्ज का कूड़ा। कितना मासूम है हिमाचल का प्रशासन।

अब तो सचिवालय को मालूम नहीं होता कि बाहर शिमला में आती-जाती सडक़ों का स्थायी बाशिंदा पॉलिथीन है। किसी ने चलती गाड़ी से फेंका, किसी ने चाकलेट डे मनाया, तो प्लास्टिक भी खुली हवा में चल गया। हर पर्यटक स्थल और बड़े शहरों में आ गई खाने की कोई न कोई चेन। अच्छी पैकिंग में बिकते व्यंजन और साथ में मुफ्त का कोल्ड ड्रिंक जब खत्म होता है, तो शहर की नालियां बताती हैं कि पर्यटन से प्लास्टिक का कितना भयानक रिश्ता है। दूध की थैलियां, ब्रेड के पैकेट और सब्जी की दुकानदारी में शरीक पॉलिथीन अब हमारे परिवेश से पुनः गलबहियां कर रहा है। सवाल नागरिक स्वच्छता से सामुदायिक व्यवहार तक आपत्तियां दर्ज कर रहा है, तो कौन भविष्य के प्रश्नों पर उत्तर खोजेगा। पॉलिथीन हमारी व्यवस्था से इस कद्र चस्पां है कि सरकारी कार्यालय भी ऐसी चुनौती के पर्याय बने हुए हैं। उदाहरण के लिए धर्मशाला स्थित जिलाधीश कार्यालय का पार्किंग हिमाचल का सबसे बड़ा पॉलिथीन स्टोर व आवारा पशुओं द्वारा फैलाई गई गंदगी का खजाना बना हुआ है।

आश्चर्य यह कि पांच कदम पर जिलाधीश सारे जिला को पॉलिथीन मुक्त और स्वच्छता का संदेश दे कर भी यह नहीं देख पाते कि अंततः हो क्या रहा है। कहने को हिमाचल में पांच नगर निगम और पचास के करीब शहरी निकाय हैं, लेकिन इनकी बाहों में फैले पॉलिथीन एक विरासत की तरह टस से मस नहीं होता। शहरों की औकात में इतना दम नहीं कि ढंग से इसका निपटारा कर सकें। यूं तो सरकारें पॉलिथीन खरीद से सडक़ निर्माण तक इसका निपटारा करने की डींगें हांकती रही हैं, लेकिन आफत की यह पुडिया हर जगह और हर वक्त उपलब्ध है। ऐसे में फिर से एक बड़े अभियान के माध्यम से इसे हटाने की नहीं, बल्कि इसकी आदत व जरूरत मिटाने की दिशा में प्रयत्न करने होंगे। पांच करोड़ पर्यटकों के लक्ष्य में नीतियां, संदर्भ और अधोसंरचना को अगर पुख्ता करने के प्रयास हो रहे हैं, तो सरकार यह व्यवस्था भी करे कि सैलानियों के आगमन से पॉलिथीन का साम्राज्य न बढ़ जाए। कूड़ा कर्कट प्रबंधन की ऐसी तस्वीर जरूरी है जहां प्लास्टिक का कचरा हमारी गतिशीलता का अपशगुन न बन जाए।

बेसहारा गोवंश को आश्रय दे प्रदेश सरकार

आशा है प्रदेश सरकार इन सुझावों को बिना देरी के व्यापक जनहित में लागू करने का प्रयत्न करेगी, ताकि किसानों की फसलों की रक्षा हो सके, सडक़ों पर यातायात ठीक हो सके और गौवंश को रैन-बसेरा प्राप्त हो सके

भारतीय सभ्यता में गाय को सदैव देवी माता स्वरूप माना जाता है। भारत में गोपालन की प्राचीन काल से ही परंपरा रही है। इसलिए उस समय घी, दूध और दही की नदियां बहती थीं। ऋषियों के आश्रम जंगलों में होते थे। वहां हजारों गउएं स्वतंत्र रूप से विचरण करती और जंगलों में चरती थीं। भगवान श्रीकृष्ण जी ने द्वापर युग में खुद गऊओं की सेवा की। इसलिए उनका एक नाम श्री गोपाल आज भी संसार भर में प्रसिद्घ है। भगवान ने मानव जाति को गाय वरदान स्वरूप दी थी, लेकिन आज का स्वार्थी मानव गाय को आफत समझ रहा है। वह दिन दूर नहीं जब गाय के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। जब गाय नहीं होगी तो किसान नहीं होगा। जब किसान नहीं होंगे तो गांव भी नहीं होंगे। जब गांव नहीं होंगे तो देश नहीं होगा। धीरे-धीरे तेल के भंडार कम हो रहे हैं। जब तेल खत्म हो जाएगा, तब खेती के लिए बैलों की जरूरत होगी, लेकिन क्या तब तक बैल बच पाएंगे? खेद है कि 33 करोड़ देवी-देवताओं को धारण करने वाली, पंचगव्य देने वाली, सूतक-पातक से बचाने वाली गाय माता आज जूठन खा रही है, पत्थर व डंडे खा रही है। भाईयो व बहनो, जिस घर में, जिस गांव में संतान के कारण मां रोती है, वहां पर कभी कल्याण नहीं हो सकता है। गाय मां है और बैल धर्म है। गाय के पंचगव्य से अनेकों प्रकार की औषधियां बनती हैं।

गऊ पूजन व गौदान का विशेष महत्त्व होता है। भैंस पूजन का महत्व नहीं है। प्रातः उठकर गाय के शरीर पर हाथ फेरो, परिक्रमा करके चरण वंदना करो तथा एक मु_ी घास या एक रोटी गाय को हर रोज दें, ऐसा करने से प्रभु के अवश्य दर्शन होते हैं। रोगी गाय को औषधि व सेवा करने वाला व्यक्ति रोगमुक्त हो जाता है। वर्तमान में गोबर से निर्मित वस्तुएं, यथा आभूषण, राखी, झूमर, मूर्तियां, गमले एवं नेम प्लेट सर्वाधिक चलन में हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहां पर गौवंश की स्थिति ठीक नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस समय में लगभग 10000 से अधिक गौवंश बेसहारा चारे तथा पानी की तलाश में इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, जो हमारे देवभूमि के लोगों के लिए बड़े ही दुःख और शर्म की बात है। पूर्व में रहे ग्रामीण पशुपालन मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग की स्थापना करके इन बेसहारा गौवंश को आश्रय देने के लिए प्रदेश में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी गऊ सैंक्चुरी और गौशालाओं की स्थापना करके बड़ा साहसिक और नेक कार्य किया है। लेखक ने सरकार के वर्तमान कृषि एवं पुशपालन मंत्री को 14.11.2023 को बेसहारा गौवंश के लिए गौसेवा आयोग द्वारा गौशालाएं व गऊ सैंक्चुरी बनाने तथा गौसेवकों की भर्ती करने बारे कुछ सुझाव एक पत्र द्वारा भेजे थे तथा उस पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री तथा अन्य को भी भेजी थी। मुख्य जरूरी सुझाव ये हैं : एक, इस समय प्रदेश में जो लगभग 10000 से ज्यादा बेसहारा गौवंश हैं, इनकी सेवा के लिए गौसेवा आयोग प्रत्येक जिले के प्रत्येक विकास खंड में तीन-तीन बड़ी गौशालाएं बनाएं, ताकि इन अभागे पालतू छोड़े हुए बेसहारा गौवंश को इनका खोया हुआ रैन-बसेरा दोबारा मिले सके। दो, इन 10000 बेसहारा गौवंश की सेवा के लिए गौसेवा आयोग 1000 गौसेवकों की भर्ती करे, यानी प्रत्येक 10 गौवंश पर एक गौसेवक नियुक्त हो, जिसकी तनख्वाह प्रति महीना 6000 रुपए हो तथा साथ में मुफ्त रिहायश और भोजन की व्यवस्था हो। तीन, इन गौसेवकों को आठ या दस साल बाद की सेवा के बाद प्रदेश सरकार अपने विभागों या बोर्डों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों में नियुक्त करने का प्रबन्ध करे।

चार, जितने भी लोगों ने प्रदेश में गाय या बैल पाल रखे हैं, उन सबकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए यानी उन सबके गौवंश कार्ड बनाए जाने चाहिएं, जैसे आदमियों के राशन कार्ड बनाए जाते हैं। यह कार्य पशुपालन विभाग द्वारा पंचायतों के सहयोग से किया जाना चाहिए। पांच, अगर कोई पशुपालक अपने गौवंश को बेसहारा छोड़ता है तो ऐसे पशुपालक को पहली बार 15000 रुपए, दूसरी बार 20000 रुपए और तीसरी बार 25000 रुपए और एक साल की सजा भी होनी चाहिए। छह, प्रदेश सरकार राज्य में गोमूत्र आधारित कोई बड़ी आयुर्वेदिक फार्मेसी स्थापित करे ताकि गौवंश पालने वालों को आर्थिक सहायता भी मिल सके और प्रदेश की जनता को आयुर्वेदिक औषधियां भी मिल सके। सात, पशुपालकों को बढिया बैल पालने पर गौसेवा आयोग द्वारा सालाना लगभग 6000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। आठ, जो शामलात भूमि सरकार के पास वनों के साथ है, वहां सरकार उस भूमि का अधिग्रहण करके या किसानों से बंजर भूमि लेकर गौशालाएं बनाए। नौ, सरकार शराब की बिक्री से अढ़ाई रुपए प्रति बोतल की सैस को बढ़ाकर 10 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से गौ कल्याण कोष के लिए निर्धारित करे। दस, प्रदेश सरकार बड़े मंदिर ट्रस्टों की आमदन के 15 प्रतिशत हिस्से को बढ़ाकर 25 प्रतिशत गौ कल्याण कोष के लिए निर्धारित करे।

ग्यारह, प्रदेश सरकार विधानसभा में कानून बनाकर गौ कल्याण कोष की बढ़ोतरी के लिए प्रत्येक विधायक तथा मंत्री से पांच-पांच हजार रुपए दान लेने की व्यवस्था शुरू करे। बारह, इसी प्रकार प्रदेश सरकार गौ कल्याण कोष के लिए प्रदेश के सारे पहली श्रेणी के अधिकारियों से 500 रुपए, दूसरी श्रेणी वालों में से 250 रुपए, तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों से 100 रुपए तथा चतुर्थ श्रेणी वालों से 50 रुपए प्रति महीना दान लेने की व्यवस्था शुरू करे। तेरह, बेसहारा गौवंश को आश्रय देने वाले गैर सरकारी गौसदनों की सहायता राशि चारे की महंगाई के कारण 700 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीना प्रति गौवंश की जाए। चौदह, गौसेवा आयोग को उपरोक्त सहायता की शर्त को 30 गौवंश से कम करके 11 गौवंश किया जाना चाहिए। आशा है प्रदेश सरकार इन सुझावों को और बिना देरी के व्यापक जनहित में लागू करने का प्रयत्न करेगी ताकि किसानों की फसलों की रक्षा हो सके, सडक़ों पर यातायात ठीक हो सके और इन बेसहारा गौवंश को इनका खोया हुआ रैन-बसेरा दोबारा से प्राप्त हो सके। गौवंश के कल्याण से निश्चित रूप से प्रदेश का भी कल्याण होगा।

रणजीत राणा

अंधे अंधा ठेलिया

पीए सिद्धार्थ

एक समय की बात है। ज़ोम्बीद्वीप में एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और संवेदनशील राजा राज्य करता था। देश में राजशाही के बावजूद लोकतंत्र में उसकी गहन आस्था थी। उसने एक संविधान के निर्माण के बाद उसे न केवल लागू करवाया बल्कि उसकी रक्षा के लिए क़ानून भी बनाया। देश का नाम भले ही ज़ोम्बीद्वीप था, परन्तु उसके लोग ज़ोम्बी नहीं थे। देश बहुधर्मी था और सभी धर्मों के लोग आपस में बड़े प्रेम, भाईचारे और सौहार्द से रहते। राजा का एक लडक़ा था। देखने में साधारण होने के बावजूद वह अपने आपको धर्मेन्द्र से कम नहीं समझता। आत्ममुग्धता का शिकार राजकुमार दिन में दस बार कपड़े बदलता। वह स्वभाव से मनमौजी, अक्ल से साधारण और नीयत से बेईमान था। झूठ बोलने में उसे विशेष आनन्द आता। धीरे-धीरे उसने झूठ बोलने में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वह दिन में एक ही व्यक्ति को दस बार मूर्ख बना सकता था। बूढ़े होते राजा ने शासन की बागडोर अपने बेटे को सौंपना चाही। परन्तु उसके खिलंदड़ स्वभाव से परेशान राजा ने सम्पूर्ण राजपाट सौंपने की बजाय पहले उसे युवराज घोषित किया। उसने सोचा कि जब राजकुमार शासन की बारीकियां सीख जाएगा तब उसे राजा घोषित करने के बाद वह जंगल की राह पकड़ लेगा।

झूठ बोलने में माहिर युवराज ने अपने पिता को यह विश्वास दिला दिया कि पूरी दुनिया में ज़ोम्बीद्वीप का डंका बज रहा है। राजा ने 'सब चंगा है' सोच कर जंगल की राह पकड़ ली। युवराज ने राजा बनने के बाद अपने मनमौज़ी स्वभाव के अनुरूप प्रजा को हांकना शुरू कर दिया। देश के सभी अमीर सेठ उसके लंगोटिया यार थे, जो केवल अपना मुनाफा कूटने में मस्त रहते। फलस्वरूप देश में बेरोजग़ारी और महंगाई बढऩे लगी, कृषि उत्पादन गिर गया और देश की आर्थिकी डगमगाने लगी। इसके बावजूद राजा अपने आपको महान सिद्ध करने के लिए अपने पुरखों को गरियाते हुए राज्य की परिसम्पत्तियां बेचता रहता। उसकी देखादेखी प्रजा भी झूठ बोलने लगी। लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को लतियाते हुए प्रजा ने विधर्मियों और कमज़ोर वर्गों को मारना-पीटना शुरू कर दिया। पर मौज-मस्ती में मगन रहने वाला राजा इतना झूठ बोलता कि धीरे-धीरे उसे यक़ीन होने लगा कि वह राजा हरीशचंद्र है। नारसिस्ट होने के अलावा अब वह मिथोमैनिक भी हो गया था। तुकबंदी में माहिर नए राजा ने लोगों को सपने बेचना शुरू कर दिए। राजा के वस्त्र विन्यास, साज-सज्जा और वृक्तता से अभिभूत बहुसंख्यक वर्ग के अधिकांश लोग उसके अंधभक्त हो गए। लेकिन अभी भी कुछ कथित बुद्धिजीवी थे, जो राजा की हाँ में हाँ मिलाने को तैयार नहीं थे।

नारसिस्ट, मिथोमैनिक और खिलंदड़ राजा के दिल में अमर होने की चाह टमाटर और प्याज़ की पैदावार कम होने पर क़ीमतों में होने वाली वृद्धि की तरह आसमानी उछाल मार रही थी। वह उठते-बैठते सोचता कि इन बुद्धिजीवियों से कैसे पार पाया जाए। उसे परेशान देखकर उसके महामंत्री ने सलाह दी कि अक्ल से अंधे जो लोग पहले ही उसके साथ हैं, उनके साथ कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं। बस राष्ट्रवाद के नाम पर छद्म शत्रु, विधर्मियों और कमज़ोरों को गरियाते हुए अंधभक्तों को सुनहरे सपने बेचने हैं। ख़ाली जेबों के बावजूद राष्ट्रवाद के नाम पर ये अंधभक्त अपनी जान तक देने की बात करने लगेंगे। महामंत्री की सलाह मानते हुए राजा ने विरोधी बुद्धिजीवियों को बिना मुक़द्दमों के जेल में डालना शुरू कर दिया। कुछ विरोधी बुद्धिजीवियों को अंधभक्तों ने राष्ट्रविरोधी बताते हुए सडक़ों पर मार दिया। कुछ जेल में मर गए। शेष बुद्धिजीवियों की अंधभक्तों के साथ मैचिंग कराने के लिए सचमुच अंधा बना दिया गया। इसके बाद उन्हें बौद्धिक रूप से अंधा बनाने के लिए गोदी माडिया के माध्यम से फेक न्यूज़ के जो छप्पन भोग परसे जाते, उनमें राजा के वैश्विक चक्रवर्ती सम्राट होने, समस्त ब्रह्मांड में उसका डंका बजने, राष्ट्र का अग्रणी होना आदि शामिल थे। राजा को अब पूरा यक़ीन हो गया था कि अब उसे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ समय बाद, समय को छोडक़र ज़ोम्बीद्वीप की समस्त प्रजा अंधत्व को प्राप्त हो चुकी थी। अब अंधे ही अंधों को ठेल रहे थे।

पीए सिद्धार्थ

इस साल घर खरीदने का अच्छा मौका, ज्यादा नहीं बढ़ेंगे दाम, जानें क्या है वजह

परिवहन विशेष न्यूज

वित्त वर्ष 2024-25 में हाई बेस इफेक्ट की वजह से घरों की बिक्री 8-10 प्रतिशत बढ़ सकती है। वहीं घरों का दाम करीब 5 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। अब डिमांड लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट से मध्य और उच्च-मध्यम आय वर्ग की ओर ट्रांसफर हो रही है। रेटिंग एजेंसी ने मौजूदा वित्त वर्ष में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए न्यूट्रल व्यू बनाए रखा है।

नई दिल्ली। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, तो इस साल खरीद सकते हैं, क्योंकि घरों की कीमत में ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद नहीं है। यह बात इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (इंड-रा) ने कही है।

इंड-रा का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024-25 में हाई बेस इफेक्ट की वजह से घरों की बिक्री 8-10 प्रतिशत बढ़ सकती है। वहीं, घरों का दाम करीब 5 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी ने मौजूदा वित्त वर्ष में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के लिए न्यूट्रल व्यू बनाए रखा है।

वित्त वर्ष 2023-24 के पहले नौ महीनों के दौरान आवासीय रियल एस्टेट मार्केट ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान ब्याज दर स्थिर रहने और कीमतें बढ़ने के बावजूद टॉप आठ रियल एस्टेट ग्रुप के लिए सालाना आधार पर बिक्री में 25 से अधिक का इजाफा हुआ है।

प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में बढ़ी इन्वेंट्री

इंड-रा में कॉर्पोरेट रेटिंग के डायरेक्टर महावीर शंकरलाल जैन का कहना है, 'ज्यादातर क्षेत्रों में घरों में दाम बढ़ रहे हैं। हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2025 में प्री-सेल ग्रोथ सालाना आधार पर 8 से 10 प्रतिशत तक रहेगी। प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में पिछले वित्त वर्ष के दौरान इन्वेंटरी का स्तर भी बढ़ गया है, क्योंकि बिक्री बढ़ने से बिल्डर्स ने नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग तेज कर दी थी।'

इंड-रा का कहना है कि ज्यादातर बिल्डर्स का पुराना स्टॉक बिक गया है। अब डिमांड बढ़ने से मौजूदा इन्वेंट्री भी काफी हद तक खत्म होने वाली है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, अब डिमांड लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट से मध्य और उच्च-मध्यम आय वर्ग की ओर ट्रांसफर हो रही है।

नहीं रहेगा वेटिंग का झंझट! रेल मंत्री बोले- सभी यात्रियों को मिलेगा कंफर्म टिकट

परिवहन विशेष न्यूज

रेल से यात्रा करने वाले कई लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी होती है। इसकी शिकायत अक्सर लोग सोशल मीडिया पर भी करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफी समय पहले बुकिंग करने के बाद भी उनका टिकट वेटिंग में ही रह जाता है। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले पांच साल में सबको कंफर्म टिकट मिलने लगेगा।

नई दिल्ली। रेल से यात्रा करने वाले कई लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी होती है। इसकी शिकायत अक्सर लोग सोशल मीडिया पर भी करते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काफी समय पहले बुकिंग करने के बाद भी उनका टिकट वेटिंग में ही रह जाता है। हालांकि, अब सरकार इस समस्या को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम रही है।

रेल मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अगले पांच वर्षों में लगभग सभी यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि रेल यात्रा करने वाले सभी लोगों को कंफर्म टिकट मिले।

तेजी से बन रहे नए रेलवे ट्रैक

केंद्रीय मंत्री ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में कहा, 'अगले पांच साल में रेलवे की क्षमता इतनी बढ़ा दी जाएगी कि जो भी रेलवे से सफर करना चाहेगा, उसे आसानी से कंफर्म टिकट मिल सकेगा।' उन्होंने यह भी कहा कि पिछले एक दशक के दौरान रेलवे में डेवलपमेंट की रफ्तार काफी तेज हुई है।

इसका उदाहरण देते हुए वैष्णव ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच केवल 17,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए गए थे। वहीं, 2014 से 2024 तक 31,000 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए। 2004 से 2014 के दौरान लगभग 5,000 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया गया, जबकि पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ है। 2004-2014 तक केवल 32,000 कोच बनाए गए। पिछले 10 वर्षों में 54,000 कोच बन गए हैं।

2026 में चलेगी पहली बुलेट ट्रेन!

रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए विभिन्न स्टेशनों के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2026 में एक सेक्शन में पहली बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद-मुंबई रूट पर बुलेट ट्रेन का काम बहुत अच्छे से चल रहा है।

इसके लिए 290 किलोमीटर से अधिक का काम पहले ही किया जा चुका है। इसके लिए आठ नदियों पर पुल बनाए गए हैं। 12 स्टेशनों पर काम चल रहा है। कई स्टेशन ऐसे हैं, जिनका काम पूरा होने वाला है। 2026 में बुलेट ट्रेन के परिचालन के लिए काम बहुत तेज गति से चल रहा है।

925 ट्रेनें प्रभावित, हजारों यात्री परेशान

परिवहन विशेष न्यूज

अंबाला में किसानों के रेल रोको आंदोलन का मंगलवार को सातवां दिन है। इस आंदोलन के चलते 925 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जिसमें 186 मेल एक्सप्रेस व 231 पेसेंजर गाड़ियां शामिल हैं और बाकी ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। ट्रेनों के प्रभावित होने के कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली भी परेशान हैं। किसानों के रेल रोको आंदोलन का असर अब लोगों के रोजगार पर भी पड़ने लगा है। एक तरफ रेल यात्री परेशान हो रहे हैं, वहीं अब स्टेशन पर यात्रियों के सहारे ही अपनी आजीविका चलाने वाले कुली भी परेशान होने लगे हैं।

अंबाला रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करने वाले मोनू ने बताया कि किसान आंदोलन की वजह से लोगों का यहां आना कम हो गया है। पहले यहां काफी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन अब पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। अब घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सुबह छह बजे से अब तक केवल 100 रुपये कमा पाए हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं, जल्द से जल्द कोई इसका समाधान निकाला जाए, ताकि हमारी भी कमाई ठीक हो सके। रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्री मनीष ने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं। पहले ट्रेन एक घंटा लेट थी, लेकिन अब आधा घंटा और लेट है, पता नहीं कब ट्रेन आएगी। सभी ट्रेनें लेट हैं। कोई कारण नहीं बता रहा है। दिल्ली जाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि ट्रेन प्रभावित होने का आकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों का रेल रोको आंदोलन कज सातवां दिन है। आंदोलन के कारण 925 ट्रेन प्रभावित हैं, जिसमें 186 मेल एक्सप्रेस और 231 पेसेंजर गाड़िया शामिल हैं और बाकी ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। 103 मालगाड़ियां भी रूट बदलकर चलाई जा रही हैं! कुल मिलाकर 1028 गाड़ियां इससे प्रभावित हो रही हैं! इस समय एक ही रूट पर गाड़ियों का परिचालन है, जिस कारण दो से चार घंटे ट्रेनें देरी से चल रही हैं! अभी नुकसान का आकलन नहीं किया गया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन पर आज एक अलग से नज़ारा भी देखने को मिला। परेशान यात्रियों को सरकार व किसानों को लेकर दो लोगों को आपस में बहस करते भी देखा गया।

इनसाइड

इस कंपनी के साथ हो गई करोड़ों की धोखाधड़ी, आज नहीं होगा चौथी तिमाही के नतीजों का ऐलान

MM Finance Fraud महिंद्रा एंड महिंद्रा (MM) की फाइनेंशियल सर्विस देने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस (Mahindra Mahindra Finance) के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले का असर कंपनी के शेयर पर भी पड़ा है। आज कंपनी द्वारा मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान किया जाना था जिसे अब टाल दिया गया है। यहां पढ़ें पूरा मामला...

नई दिल्ली। ऑटोमोबाइल सेक्टर की दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) की फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस (Mahindra & Mahindra Finance) के साथ फ्रॉड होने का मामला सामने आया है। बता दें कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस गैरबैंक वित्तीय कंपनी (NBFC) है। इस फ्रॉड के बारे में पता चलने के बाद कंपनी ने मार्च तिमाही के नतीजों को टाल दिया है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने नहीं बताया है कि वह किस दिन तिमाही नतीजों का ऐलान करेगी। महिंद्रा फाइनेंस ने स्टॉक एक्सचेंज पर रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि आज होने वाले बोर्ड मीटिंग में बॉरोइंग लिमिट को बढ़ाने और फंड जुटाने पर विचार करेगी। कंपनी ने यह भी बताया कि वह आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के तिमाही नतीजों का ऐलान करेगी। इसकी वजह कंपनी ने बताया कि उनके नार्थ ईस्ट के एक ब्रांच में 150 करोड़ रुपये के जालसाजी का मामला सामने आया है।

फिर बढ़ सकती है महंगाई, रिजर्व बैंक के बुलेटिन में क्यों कही गई यह बात?

परिवहन विशेष न्यूज

रिजर्व बैंक (RBI) ने अपने अप्रैल बुलेटिन में महंगाई बढ़ने का अंदेशा जताया है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि मौसम की विषम परिस्थितियां कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही दुनिया कई हिस्सों में भूराजनीतिक तनाव भी काफी लंबा खिंच गया है। इससे क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव लगा रहेगा। इन सबका महंगाई पर बुरा असर पड़ेगा।

मुंबई। रिजर्व बैंक (RBI) के अप्रैल बुलेटिन में महंगाई बढ़ने का अंदेशा जताया है। इसमें कहा गया है कि मौसम की विषम परिस्थितियां कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही, दुनिया कई हिस्सों में भूराजनीतिक तनाव भी काफी लंबा खिंच गया है। इससे क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव लगा रहेगा। इन सबका महंगाई पर बुरा असर पड़ेगा।

महंगाई पर रहती है RBI की नजर

मार्च में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर रिटेल इंफ्लेशन में मामूली गिरावट देखने को मिली। यह दो महीनों तक औसतन 5.1 फीसदी रहने के बाद मार्च में घटकर 4.9 फीसदी हो गई। रिजर्व बैंक अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में CPI डेटा को काफी अहमियत देता है।

इसने मुद्रास्फीति से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते फरवरी 2023 से प्रमुख ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया और यह 6.5 प्रतिशत पर बरकरार है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बदलाव करने के लिए महंगाई के काबू में आने का इंतजार करेगा।

जीडीपी ग्रोथ अच्छी रहने का अनुमान

RBI के बुलेटिन में छपे 'State of the Economy' पर लेख में कहा गया है कि 2024 की पहली तिमाही में वैश्विक विकास की गति बरकरार रही है। साथ ही, विश्व व्यापार के लिए नजरिया सकारात्मक हो रहा है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में ट्रेजरी यील्ड और बॉन्ड रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम हो रही हैं।

लेख में कहा गया है, 'भारत में रियल जीडीपी ग्रोथ जारी रहने के पक्ष में माहौल बन रहा है। यहां निवेश की अच्छी डिमांड है। बिजनेस और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी काफी अच्छा है।' हालांकि, आरबीआई ने कहा कि बुलेटिन लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और वे हमारे विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

भारत पे ने लॉन्च की नई पेमेंट डिवाइस, अब एक ही मशीन करेगी इतने काम

परिवहन विशेष न्यूज

BharatPe ने आज BharatPe One लॉन्च किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसकी योजना पहले चरण में लगभग 100 शहरों में उत्पाद लॉन्च करने की है। अगले 6 महीनों के दौरान इसे लगभग 450 शहरों तक बढ़ाया जाएगा। बयान में कहा गया उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस पोर्टेबल डिजाइन और व्यापक लेनदेन डैशबोर्ड के साथ भारतपे वन ऑफलाइन व्यापारियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है।

नई दिल्ली। भारतीय फिनटेक कंपनी BharatPe ने आज यानी मंगलवार को BharatPe One लॉन्च किया है। ये एक ऑल-इन-वन पेमेंट प्रोडक्ट है, जो POS (प्वाइंट ऑफ सेल), क्यूआर कोड और स्पीकर को एक डिवाइस में इंटीग्रेट करता है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

BharatPe ने बनाया ये प्लान

कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसकी योजना पहले चरण में लगभग 100 शहरों में उत्पाद लॉन्च करने की है। अगले 6 महीनों के दौरान इसे लगभग 450 शहरों तक बढ़ाया जाएगा। कंपनी ने कहा कि हाई-डेफिनिशन टचस्क्रीन डिस्प्ले, 4जी और वाई-फाई कनेक्टिविटी से लैस और नवीनतम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा संचालित, BharatPe One बेहतर प्रदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता है।

एक मशीन करेगी इतने काम

बयान में कहा गया, ₹उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, पोर्टेबल डिजाइन और व्यापक लेनदेन डैशबोर्ड के साथ, भारतपे वन ऑफलाइन व्यापारियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करता है।₹

भारतपे वन को व्यापारियों के लिए लेनदेन को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड की एक विस्तृत श्रृंखला में गतिशील और स्थिर क्यूआर कोड, टैप-एंड-पे और पारंपरिक कार्ड भुगतान विकल्पों सहित बहुमुखी भुगतान स्वीकृति विकल्प प्रदान करता है।

भारतपे के सीईओ नलिन नेगी ने कहा, ₹एक लागत प्रभावी डिवाइस में कई कार्यक्षमताओं को जोड़कर, हम विभिन्न क्षेत्रों में छोटे और मध्यम व्यवसायों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप एक व्यापक समाधान प्रदान कर रहे हैं।

21 दिनों में रिकॉर्ड लोगों ने किया ट्रेन से सफर, इतने यात्रियों को कैसे संभाल रहा रेलवे

परिवहन विशेष न्यूज

रेलवे ने पहले भी कहा था है कि उसने रिकॉर्ड संख्या में अतिरिक्त ट्रेन यात्राएं संचालित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं जो पिछले साल की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक होगा। अधिकारी के अनुसार गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि के मद्देनजर कई विशेष ट्रेनें शुरू करके और स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार करके विस्तृत उपाय किए हैं।

नई दिल्ली। छुट्टियों का सीजन हर बार रेलवे के सामने नई चुनौतियां लेकर आता है। अतिरिक्त ट्रेनें चलाने से लेकर स्टेशनों पर उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती तक, तमाम इंतजाम रेलवे को करने पड़ते हैं। इस साल भी स्थीति कुछ अलग नहीं है। छुट्टियों का सीजन अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुआ है और रेलवे इन तमाम चुनौतियों से दो-चार होना पड़ रहा है।

अब भारतीय रेलवे ने खुद इस बात की तस्दीक की है यात्री सेवाओं को लेकर उसके दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को अपने परिचालन और यात्री सेवाओं पर दबाव को रेखांकित करते हुए रेलवे ने बताया था कि 1 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक 41 करोड़ से अधिक लोग ट्रेन की यात्रा कर चुके हैं।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा था, ''रेलवे ने 1-21 अप्रैल के दौरान 41.16 करोड़ लोगों को यात्रा कराई। पिछले वीकेंड, यानी 20 और 21 अप्रैल को 3.38 करोड़ यात्रियों ने विभिन्न गंतव्यों के लिए रेल यात्रा की। इससे पिछले सप्ताह में कुल 13.69 करोड़ यात्रियों ने रेल से सफर किया।''

रेलवे ने पहले भी कहा था है कि उसने रिकॉर्ड संख्या में अतिरिक्त ट्रेन यात्राएं संचालित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 43 प्रतिशत अधिक होगा। अधिकारी के अनुसार गर्मी की छुट्टियों के दौरान यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि के मद्देनजर कई विशेष ट्रेनें शुरू करके और स्टेशन पर सुविधाओं में सुधार करके विस्तृत उपाय किए हैं। जोनल रेलवे को रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अधिकारी ने बताया कि सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण की विस्तृत व्यवस्था की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों को सभी गतिविधियों की निगरानी करने और भीड़ को व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करने के लिए इन स्टेशनों पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है।

जनरल क्लास के डिब्बों में प्रवेश के लिए किसी तरह की भगदड़ जैसी सथिति न बने, इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सामान्य 'कतार प्रणाली' यानी यात्रियों को लाइन में लगवाना सुनिश्चित करने के लिए स्टेशनों पर पर्याप्त कार्यबल तैनात करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर कड़ी नजर रखने और यात्रियों को वास्तविक समय पर सहायता प्रदान करने के लिए सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष में कुशल आरपीएफ कर्मचारियों को तैनात किया गया है। एक आरपीएफ अधिकारी ने कहा, ₹भारी भीड़ के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति से बचने के लिए भीड़ को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) और आरपीएफ कर्मचारियों को फुट-ओवर ब्रिज पर तैनात किया जाता है।₹ उन्होंने कहा कि यात्रियों को पूछताछ में मदद के लिए अतिरिक्त हेल्प डेस्क और काउंटर भी स्थापित किए गए हैं।

सोना-चांदी खरीदने का 'सुनहरा' मौका, गोल्ड 1450 रुपये और सिल्वर 2300 हुआ सस्ता

कारोबारी सत्र खत्म होने पर सोने की कीमत में 1450 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। वहीं चांदी की कीमत में भी 2300 रुपये गिरकर प्रति किलो 83500 रुपये पर आ गई जो सोमवार को 85800 रुपये प्रति किलो पर थी। सोने और चांदी कीमत में यह कटौती अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिले सुस्ती के रुझान के चलते देखने को मिली है।

नई दिल्ली। सोने और चांदी कीमत में भारी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को कारोबारी सत्र खत्म होने पर सोने की कीमत में 1450 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 72200 रुपये पर बंद हुआ। वहीं, चांदी का भाव भी 2300 रुपये टूटकर 83,500 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

सस्ता हुआ सोना-चांदी : एचडीएफसी सिक्योरटीज के मुताबिक, सोने की कीमत 1450 रुपये गिरकर 72200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। सोमवार को सोने की कीमत 73650 रुपये थी। वहीं, चांदी की कीमत में भी 2300 रुपये गिरकर प्रति किलो 83,500 रुपये पर आ गई, जो सोमवार को 85800 रुपये प्रति किलो पर थी। एचडीएफसी सिक्योरिटी के सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट सौमिल गांधी ने बताया कि 24 कैरेट सोने की कीमत में यह गिरावट विदेशी मार्केट से मिले सुस्त रुझान के चलते देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो सोना पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले 55 डॉलर की गिरावट के साथ 2,310 डॉलर प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रहा है।

'इंडी गठबंधन के आधे नेता जेल में, आधे 'बेल' पर'

परिवहन विशेष न्यूज

टीकमगढ़। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों के गठबंधन 'इंडिया' पर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन के आधे नेता जेल में, आधे 'बेल' पर हैं और चार जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और तेज होगी। जेपी नड्डा मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी उपस्थित रहे।

जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति और सोच बदल गई है। 10 साल पहले सब कहते थे कि सब ऐसा ही चलेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। आज सामान्य आदमी भी कह रहा है कि देश बदल गया है। विकसित भारत बनाने के लिए मजबूत सरकार चाहिए, जो निर्णय ले सके। देश में स्थिर सरकार बनने से अंतर ये आया है कि, जो हम 1951 से एक देश में दो निशान नहीं चलने वाला नारा दे रहे थे, वो फलीभूत हुआ है।

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत दो साल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि जनता को इस बार दो विचारधाराओं के बीच चुनाव करना है। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास करने में लगे हुए लोग हैं, दूसरी ओर परिवारवादी हैं, जो अपने परिवार और भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हैं। इंडी गठबंधन दो बातों के लिए बना है, एक तो ऐसे परिवारवादी हैं जो अपने परिवार को बचाने में लगे हैं, दूसरे भ्रष्टाचार को बचाने में लगे हैं। इन्हें और कोई काम नहीं है। सारे घोटालेबाज एक दूसरे को बचाने में लगे हैं।

उन्होंने विपक्षी दलों की रैलियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये रैली करते हैं तो दो कुर्सियां खाली रखते हैं और कहते हैं कि उनके दो मुख्यमंत्री जेल गए हैं, उनके लिए दो कुर्सी खाली रखी हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि सभी लोग चार जून का इंतजार करें, उसके बाद पीएम मोदी की भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम और तेज होगी और और लोगों को जेल होगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन के जेल जाने वाले और जमानत पर चल रहे नेताओं के नाम गिनाते हुए कहा कि गठबंधन के आधे नेता 'बेल' पर हैं और आधे जेल में हैं।

अब चीन की खैर नहीं! अगले साल तक भारत को मिल जाएगी एस-400 मिसाइल

रूस सतह से हवा में मार करने वाली एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली की अंतिम खेप की आपूर्ति करने में लगातार देरी कर रहा है।चीन की ओर से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अपनी वायु शक्ति क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिसाइल प्रणालियों की खरीद कर रहा है।भारत ने रूस से पांच मिसाइल प्रणालियों की खरीद के लिए 2018 में 5 .5 अरब अमेरिकी डालर का सौदा किया था।

नई दिल्ली। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस सतह से हवा में मार करने वाली एस-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली की अंतिम खेप की आपूर्ति करने में लगातार देरी कर रहा है। हालांकि, आधिकारिक सूत्रों की मानें तो नई समय सीमा के तहत भारत को प्रणाली की दो इकाइयां अगले साल तक मिल जाएंगी।

चीन की ओर से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत अपनी वायु शक्ति क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिसाइल प्रणालियों की खरीद कर रहा है। भारत ने रूस से पांच मिसाइल प्रणालियों की खरीद के लिए 2018 में 5.5 अरब अमेरिकी डालर का सौदा किया था। इनमें से तीन लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों को रूस भारत को सौंप चुका है।

2021 में भेजी थी पहली यूनिट

रूस ने दिसंबर 2021 में मिसाइल सिस्टम की पहली इकाई की आपूर्ति की थी। इन्हें चीन की सीमा के कुछ हिस्सों के साथ-साथ पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जा चुका है। सूत्रों को मानें तो भारत को रूस निर्मित दो युद्धपोतों में से पहले युद्धपोत तुशिल की आपूर्ति सितंबर में मिलने की उम्मीद है और दूसरे युद्धपोत तमल की आपूर्ति रूस द्वारा जनवरी में की जाएगी।

हालांकि, पहले दोनों जहाजों की आपूर्ति 2022 तक होनी थी लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति में लगातार देरी हो रही है। रूस 2018 में हुए चार युद्धपोत सौदे के तहत स्टील्थ युद्धपोत की आपूर्ति कर रहा है और शेष दो भारत में बनाए जा रहे हैं।

लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, आंध्र प्रदेश में इन पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया

लोकसभा चुनाव के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के डीजीपी इंटेलिजेंस पी सीतारमनजनेयुलु का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को बुधवार को दोपहर 3 बजे तक 3 एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल भेजने के लिए कहा है।

अमरावती। लोकसभा चुनाव के बीच भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के डीजीपी इंटेलिजेंस, पी सीतारमनजनेयुलु का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को बुधवार को दोपहर 3 बजे तक 3 एडीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारियों का एक पैनल भेजने के लिए कहा है। इसके अलावा, चुनाव आयोग ने विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त कांथी राणा टाटा और हैदराबाद साउथ जोन के डीसीपी पी साई चैतन्य का भी तबादला कर दिया है।

जनता का ध्यान भटका रही सरकार

परिवहन विशेष न्यूज

चित्रदुर्ग। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया है। प्रियंका ने कहा कि आज देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हमारे 70 करोड़ भाई-बहन बेरोजगार हैं। केंद्र में 30 लाख पद खाली हैं लेकिन उसे भरा नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई- आम लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है लेकिन हमारी सरकार देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज की तारीख में केंद्र सरकार देश की सारी संपत्ति केवल कुछ ही लोगों को दे रही है। आज किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा है, लेकिन उद्योगपतियों का करोड़ों माफ हो रहा है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के पब्लिक सेक्टर को जिस तरह से बड़े घरानों को दिया जा रहा है, वह पूरा देश देख रहा है। प्रियंका गांधी ने विपक्ष दलों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई से लेकर कांग्रेस के बैंक खाते सील किए जाने के मुद्दे तक को उठाया। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में गड़बडियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया. सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सारा डाटा सामने आया।

दान देने वाले का नाम क्यों छिपाया

प्रियंका गांधी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं, बल्कि नोटबंदी के माध्यम से भी देश को धोखा देने का काम किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड और नोटबंदी से केवल काले धन को सफेद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड काला धन पर रोक लगाने के लिए लाया गया तो उसमें दान देने वाले का नाम क्यों छिपाया गया?

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान की दिलाई शपथ

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन भीलवाड़ा तथा संगम विश्वविद्यालय के एनसीसी एनएसएस के संयुक्त तत्वाधान में सभी युवा छात्र छात्राओं को तथा पहली बार वोट डालने जा रहे विभिन्न आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदान करने का संकल्प दिलाया।भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी आईएएस निवृत्ति सोमनाथ द्वारा लगभग 450 से अधिक युवाओं, छात्र-छात्राओं, फैकेल्टी, स्टाफ को मतदान करने की तथा दूसरों को मतदान कराने की शपथ दिलाई ।साथ ही युवाओं को मतदान का महत्व बताया । आईएएस निवृति सोमनाथ ने बताया की किस तरह देश के निर्माण में हमारा कीमती वोट भागीदारी निभाता है तथा देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकता है।संगम विश्वविद्यालय स्वीप कार्यक्रम नोडल अधिकारी डा राजकुमार जैन ने बताया की इस अवसर पर एनसीसी भीलवाड़ा के कमान अधिकारी लेफ्टीनेंट कर्नल तेजेंद्र शर्मा, संगम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करूणेश सक्सेना, प्रो प्रेसिडेंट प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्रही, रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता तथा एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलिंटियर आदि उपस्थित थे।

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भाजपा कार्यालय पर लिया चुनावी फीडबैक, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत अभिनंदन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम अपने अल्प प्रवास पर भीलवाड़ा पहुंचे। भाजपा जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं मांडल विधायक उदयलाल भडाना की विशिष्ट उपस्थिति में पदाधिकारियो एवं कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत, अभिनंदन किया। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि गृह राज्य मंत्री बेढम ने लोकसभा चुनाव के संबंध में चर्चा करते हुए फीडबैक लिया और चुनाव प्रचार एवं व्यवस्थाओं को लेकर सुझाव भी दिए। उन्होंने बूथ मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष रणनीति बनाने की आवश्यकता जताई। इस अवसर पर जिला मंत्री सुरेंद्र सिंह मोटरास, गोपाल तेली, जिला कोषाध्यक्ष ललित अग्रवाल, ओबीसी मोर्चा प्रदेश मंत्री नंदलाल गुर्जर, जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया, जिलाध्यक्ष प्रवास प्रमुख मनोज बुलानी, रितुशेखर शर्मा, मनीष जांगिड़ सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मतदाता परिचय-पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का नाम, पता, क्रमांक, निर्वाचक नामावली में मतदाता क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है। सभी मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड एवं वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है। फोटोयुक्त वोटर स्लिप को जानकारी/मार्गदर्शन के लिये उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं। यदि फोटोयुक्त ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान अधिकारी को दिखाना होगा।

भाजपा ओबीसी मोर्चा का सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन हमीरगढ़ में आयोजित हुआ

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी भीलवाड़ा द्वारा सामाजिक सम्मेलन आज हमीरगढ़ में शनि महाराज के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया

जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राजस्थान चंपालाल गेदर, भीलवाड़ा लोकसभा सह प्रभारी गजपाल सिंह राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह, ओबीसी मोर्चा जिला प्रभारी बद्री सामरिया, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री नंदलाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे के जिला अध्यक्ष भगवत सिंह राठौड, अध्यक्ष भाजपा मंडल हमीरगढ़ लालाराम गाडरी, लोकसभा चुनाव मैं आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया, इस अवसर पर चंपालाल गेदर को कार्यकर्ताओं ने तलवार भेंट की एवं श्रवण सिंह बगड़ी को कार्यकर्ता द्वारा लिखी गई कविता की फ्रेम भेंट की गई

भाजपा जिला मीडिया संयोजक महावीर समदानी में जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक सम्मेलन में सभी अतिथियों ने एक स्वर में कहां की आगामी आने वाली 26 अप्रैल को अपने मतदान का प्रयोग कर कमल के निशान पर बटन दबाकर बीजेपी प्रत्याशी को विजय बनाने की अपील की इसमें समस्त कार्यकर्ता जिला मंत्री गोपाल तेली, मनोज बुलानी, हमीरगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रेखा की परीहार, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष शंकर जाट, मनीष जांगिड़, दुलीचंद गाडरी यशवर्धन सैन जयदीप सिंह, मंडल महामंत्री जगदीश वैष्णव, विष्णु ओझा हरलाल सालवी, ओबीसी मोर्चा के हमीरगढ़ मंडल अध्यक्ष लादू जाट, पूर्व महामंत्री रतन मंडोवरा, शंकर गुर्जर, भैरू जाट शैलेंद्र नाथ, अभिषेक व्यास, कैलाश सोनी, मोहित छिपा, किशन सिंह, कैलाश तेली, नारायण जाट, राधेश्याम सोनी, तैली, समस्त कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे।

'अपना घर दुरुस्त करो, गैरजरूरी महंगी दवाएं लिखते हैं डॉक्टर', सुप्रीम कोर्ट ने IMA पर भी उठाया सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट में आइएमए की पैरोकारी कर रहे वकील पीएस पटवालिया से कहा कि किसी की ओर उंगली उठाते वक्त ध्यान रखें कि चार उंगलियां आपकी ओर हैं। आइएमए के सदस्यों के अनैतिक आचरण की कई बार शिकायतें आपके पास आई होंगी उन पर क्या कार्रवाई की गई। पीठ ने कहा कि हम आपकी तरफ भी निशाना कर सकते हैं।

नई दिल्ली। पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन की शिकायत करने वाली इंडियन मेडिकल एसोशिएसन (आइएमए) को भी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को घेर लिया। कोर्ट ने आइएमए से कहा कि उन्हें भी अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्हें अपने सदस्यों के अनैतिक आचरण पर ध्यान देना चाहिए, जो महंगी और गैरजरूरी दवाइयां लिखते हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सुनवाई का दायरा बढ़ाते हुए एफएमसीजी कंपनियों को भी शामिल कर लिया है।

बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी गई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफएमसीजी भी भ्रामक विज्ञापन दे रही हैं, जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यों को मेडिसिन एंड ड्रग्स एक्ट के नियम 170 के तहत कार्रवाई न करने के लिए अगस्त 2023 में लिखे गए पत्र पर जवाब मांगा है। उधर बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने जब कोर्ट को बताया कि उनकी ओर से अखबारों में बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगी गई है तो कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आपकी माफी का आकार भी आपके विज्ञापन जितना बड़ा है।

लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा जनहित का मुद्दा

कोर्ट ने कहा कि माफी बड़ी छपनी चाहिए जो दिखाई दे। ये टिप्पणियां और आदेश न्यायमूर्ति हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन के मामले में दाखिल आइएमए की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने मंगलवार को यह भी साफ किया कि कोर्ट के निशाने पर कोई विशेष कंपनी या व्यक्ति नहीं है। पीठ ने कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा जनहित का मुद्दा है। उपभोक्ताओं के व्यापक हित का मुद्दा है। लोगों को पता होना चाहिए कि वे किस रास्ते पर जा रहे हैं। कैसे और क्यों उन्हें गुमराह किया जा सकता है। अधिकारी इसे रोकने के लिए कैसे काम कर रहे हैं।

कोर्ट ने आइएमए से पूछे तीखे सवाल

सुनवाई के दौरान कोर्ट में आइएमए की पैरोकारी कर रहे वकील पीएस पटवालिया से कहा कि किसी की ओर उंगली उठाते वक्त ध्यान रखें कि चार उंगलियां आपकी ओर हैं। आइएमए के सदस्यों के अनैतिक आचरण की कई बार शिकायतें आपके पास आई होंगी, उन पर क्या कार्रवाई की गई। पीठ ने कहा कि हम आपकी तरफ भी निशाना कर सकते हैं। पटवालिया ने कहा कि वह इस पर ध्यान देंगे। पटवालिया के सुझाव पर कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को भी मामले में पक्षकार बनाया।

एमएमसीजी पर भी निगाह टेढ़ी

पीठ ने कहा ड्रग एंड मैजिक रेमिडी एक्ट को लागू करने पर बारीकी से विचार किये जाने की जरूरत है। यह मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूद प्रस्तावित अवमाननाकर्ता (बाबा रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि) तक ही सीमित नहीं बल्कि सभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों तक फैला हुआ है, जो कई बार भ्रामक विज्ञापन जारी करती हैं जिससे जनता भ्रमित होती है। विशेष तौर पर शिशु, बच्चे प्रभावित होते है और बुजुर्ग इन भ्रमित विज्ञापनों को देखकर दवाइयां लेते हैं। जनता को धोखे में नहीं रहने दिया जा सकता।

भ्रामक विज्ञापनों पर नजर जरूरी

कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य की लाइसेंसिंग ऑथोरिटी से कहा कि वे भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए खुद को सक्रिय करें। पीठ ने कहा कि प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी होने वाले भ्रामक विज्ञापनों को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि मामले में उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पक्षकार बनाया जाए जो ड्रग एवं मैजिक रेमिडी एक्ट, ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट व कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन देखें।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023